RNI No. DELMUL/2012/47011

09 जुलाई, 2026 बुधवार

नई दिल्ली
मूल्य : 01 रुपए
पृष्ठ : 08
वर्ष : 14
अंक : 98

अनोखे अंदाज़ और निराले तेवर के साथ इन्साफ की डगर पर

टाइम्स ऑफ़ पीडिया

www.timesofpedia.com Email : timesofpedia@gmail.com

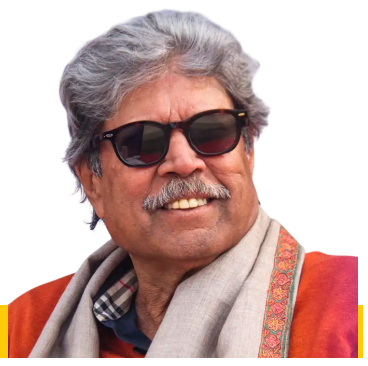

युवराज को पिता के बयानों के लिए माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं : कपिल देव 07

दोनों ने अनेक क्षेत्रों में समझौते किये : मोदी

भारत और इंडोनेशिया की साझेदारी में सुनहरे अध्याय की शुरूआत

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत और इंडोनेशिया ने अपनी समग्र रणनीतिक साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू करते हुए रक्षा, सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, समुद्री क्षेत्र, प्रौद्योगिकी और कृषि आदि क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के समझौते किये हैं।

वेब वार्ता, नई दिल्ली

इंडोनेशिया की तीन दिन की यात्रा पर गए श्री मोदी ने मंगलवार को राजधानी जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में कहा कि आज से भारत और इंडोनेशिया की साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा कि 2018 में बनी हमारी समग्र रणनीतिक साझेदारी आज एक नई उड़ान ले रही है। उन्होंने कहा, हम विकास, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी संस्कृति और शिक्षा हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है, आज से भारत-इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत कर रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने आज रक्षा आदान-प्रदान आपदा प्रबंधन और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा आज हुए समझौतों से भारत की गुणवत्तापूर्ण और किफायती दवाएं अब इंडोनेशिया के नागरिकों को और सहजता से उपलब्ध होंगी।

प्रधानमंत्री ने मौजूदा परिस्थितियों में प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों देशों ने महत्वपूर्ण खनिजों और इस्पात के क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने के लिए एक अहम समझौता किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की कंपनियों के बीच इस्पात और दुर्लभ मैग्नेट को लेकर साझेदारी की नई शुरूआत हो रही है। श्री मोदी ने कहा कि यह बहुत अच्छी बात है कि अब भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई का इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ एकीकरण होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे व्यापार सुगमता बढ़ेगी और पर्यटन क्षेत्र को भी लाभ होगा। उन्होंने कहा कि दोनों देश गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की ऐतिहासिक इंडोनेशिया यात्रा का शताब्दी वर्ष धूम-धाम से मनाएंगे। भारत-इंडोनेशिया, इस शताब्दी वर्ष को ह्यटैगोर और देवान्तरा कल्चरल एण्ड एजुकेशनल डिप्लोमेसी। ईयरह्व के रूप में मनाएंगे।

दुनिया के कुछ हिस्सों में चल रहे टकराव पर श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक उथल-पुथल के इस दौर में भारत का मानना है कि संवाद और कूटनीति की भूमिका, पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने कहा कि फिलस्तीन के विषय पर हम 'दो देश' समाधान और दीर्घावधि शांति का समर्थन करते हैं।

इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया मोदी को

वेब वार्ता, नई दिल्ली। इंडोनेशिया ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'बितांग आदिपूर्ण' से नवाजा है। इंडोनेशिया की तीन दिन की यात्रा पर गए श्री मोदी ने मंगलवार को इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता की, वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में बताया कि उन्हें इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में श्री मोदी को इस सम्मान से नवाजा। श्री मोदी ने कहा, आज सुबह, मुझे बहुत स्नेह के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया है। ये सम्मान कोटि-कोटि भारतवासियों का है... इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है, भारत और इंडोनेशिया के ऐतिहासिक और आत्मीय संबंधों का है। मैं प्रेसिडेंट प्रबोवो जी, इंडोनेशिया की सरकार और यहां की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अब तक दुनिया भर के 34 देशों ने श्री मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है।

राम मंदिर ट्रस्ट ने दिखाया खजाना

अफवाहों और विरोधियों को मिला करारा जवाब

वेब वार्ता, अयोध्या। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के आरोपों के बीच, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इन दावों को जोरदार ढंग से खारिज कर दिया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि ने मंगलवार को घोषणा की कि भक्तों द्वारा दान किया गया 32 किलोग्राम से अधिक सोना और 1,518 किलोग्राम से अधिक चांदी सहित अन्य बहुमूल्य वस्तुएं पूरी तरह सुरक्षित हैं। उन्होंने बताया कि दान की गई सभी 2,926 कीमती चीजें, जिसमें हीरा जड़ा हार भी शामिल है, सुरक्षित हैं और उनका विधिवत हिसाब रखा गया है, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गिरि का यह बयान विरोधियों और अफवाहें फैलाने वालों को करारा जवाब है।

इसके पहले सोमवार को, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मीडिया के सामने दान की गई कई अद्भुत वस्तुएं प्रदर्शित की थीं। इसमें सोने की रामचरितमानस, एक भव्य हीरा जड़ित हार, चांदी की चरण पादुकाएं और चांदी की काकभुशुंडी की कलाकृति शामिल थीं। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गिरि ने मंगलवार को इन प्रदर्शनों के बाद दान का विस्तृत ब्यौरा जारी किया। ट्रस्ट ने पुष्टि की कि इन कीमती सामानों में सोना, चांदी और हीरे जड़ित गहने, धार्मिक वस्तुएं, मुकुट, हार, चांदी की ईंटें और प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद से भक्तों द्वारा भेंट की गई अन्य वस्तुएं शामिल हैं। प्रत्येक दान का विस्तृत रिकॉर्ड रखा गया है, जिसमें दानकर्ता का विवरण, तारीख और अन्य आवश्यक जानकारियां दर्ज हैं। कोषाध्यक्ष गिरि ने अफवाहों को खारिज कर दान की गई चांदी की काकभुशुंडी की मूर्ति का भी उल्लेख कर बताया कि यह सुरक्षित है। उन्होंने सोने के दान का विस्तृत लेखा-जोखा पेश किया। 31 मार्च 2024 तक 16.765 किलोग्राम सोना मिला, वर्ष 2024-25 में 10.445 किलोग्राम और 2025-26 में 5.050 किलोग्राम प्राप्त हुआ, जिससे 31 मार्च 2026 तक सोने की कुल मात्रा 32.259 किलोग्राम हो गई। चांदी के संबंध में, कोषाध्यक्ष गिरि ने बताया कि ट्रस्ट के पास 1518.925 किलोग्राम चांदी और चांदी जैसी वस्तुएं मौजूद हैं, जिसमें दान की गई चांदी को सरकारी देखरेख में पिघलाने के बाद प्राप्त 849.272 किलोग्राम शुद्ध चांदी भी शामिल है।

संक्षिप्त वार्ता

4 दिन में 85 हजार से अधिक भक्तों ने किए बाबा बफार्नी के दर्शन

श्रीनगर। अमरनाथ यात्रा के शुरूआती चार दिनों में श्रद्धालुओं की भारी आस्था देखने को मिली है। अब तक 85,779 से अधिक श्रद्धालु पवित्र गुफा मंदिर में बाबा बफार्नी के दर्शन कर चुके हैं। सोमवार को अकेले 28,818 श्रद्धालुओं ने 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र गुफा पहुंचकर पूजा-अर्चना की। प्रशासन के अनुसार यात्रा सुचारु रूप से जारी है और हर दिन श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सोमवार को कई इलाकों में बारिश होने के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ। बालटाल और पहलगाम, दोनों मार्गों से श्रद्धालु कठिन चढ़ाई पार कर गुफा तक पहुंचे और दर्शन किए। दर्शन के बाद बड़ी संख्या में यात्री बालटाल मार्ग से सुरक्षित बेस कैंप लौट आए। अधिकारियों का कहना है कि पहलगाम मार्ग से नुनवान बेस कैंप तक लौटने में तीन से चार दिन लग जाते हैं, जबकि बालटाल मार्ग अपेक्षाकृत कम समय में वापसी की सुविधा देता है। इसी कारण अधिकांश श्रद्धालु लौटते समय बालटाल मार्ग को प्राथमिकता दे रहे हैं।

गुजरात के कई शहर बने दरिया, सूरत में स्कूलों की छुट्टी

नई दिल्ली। आर्थिक राजधानी मुंबई और उसके आस-पास के इलाकों में मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर ऐसा कहर बरपाया है कि पूरा जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के चलते गुजरात के कई शहर नदी में तब्दील होते नजर आए हैं, जहां जलभराव की स्थिति बनी हुई है। सूरत शहर में अतिवर्षा के चलते स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है।

सोमवार को मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में हुई इस भारी बारिश की वजह से रेल, सड़क और हवाई सेवाएं लगभग ठप पड़ गईं। इस प्राकृतिक आपदा ने भारत के सबसे बड़े कारोबारी शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है, जिससे शुरूआती अनुमानों के मुताबिक 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार, पिछले तीन से चार दिनों में बारिश से जुड़ी विभिन्न घटनाओं में कुल 13 लोगों की जान जा चुकी है। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने आपातकालीन कदम उठाए हैं।

नौसेना को मिलेगा स्वदेशी स्टेल्थ युद्धपोत महेंद्रगिरि

वेब वार्ता, विशाखापत्तनम। भारतीय नौसेना 11 जुलाई को स्वदेशी स्टेल्थ युद्धपोत महेंद्रगिरि को अपने बेड़े में शामिल करेगी। यह प्रोजेक्ट-17ए श्रेणी का छठा युद्धपोत है, जिसका निर्माण मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स ने किया है।

युद्धपोत में 75 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। यह अत्याधुनिक सतह से सतह और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के साथ-साथ उन्नत एंटी-सबमरीन युद्ध प्रणाली से लैस है। महेंद्रगिरि के शामिल होने से भारतीय नौसेना की समुद्री सुरक्षा और सामरिक क्षमता को और मजबूती मिलेगी। यहां बताते चलें कि इसे मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स द्वारा बनाया गया है।

इसमें 75 फीसद से अधिक स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। इसमें सतह से सतह और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और एंटी-सबमरीन सिस्टम को एड किया गया है।

चीन में भूस्खलन के मलबे में 33 लोग दबे, 17 को बचाया, 16 अब भी लापता

बीजिंग। चीन के पश्चिमी गांसू प्रांत के पहाड़ी इलाके में मंगलवार को भूस्खलन में 33 लोग मलबे में दब गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 17 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, जबकि 16 अब भी लापता बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सभी प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द बचाने के लिए हरसंभव प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस बीच सेंट्रल चीन के हुबेई प्रांत में सोमवार रात आए तेज तूफान और आंधी-बारिश से कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 275 लोग घायल हुए हैं। एक व्यक्ति अब भी लापता है।

गुजरात सीरियल ब्लास्ट मामले में 38 दोषियों को फांसी और 11 को उम्रकैद

वेब वार्ता, अहमदाबाद। अहमदाबाद में 2008 में हुए सीरियल बम ब्लॉस्ट मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने स्पेशल कोर्ट के आदेश पर मुहर लगा दी। इस मामले में 38 दोषियों को दी गई फांसी की सजा बरकरार रखी गई है, वहीं 11 की आजीवन कारावास की सजा भी बरकरार रहेगी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पीड़ितों को मुआवजा देने का आदेश भी दिया है। धमाकों में मारे गए 56 लोगों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए और 200 से ज्यादा घायलों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा।

बता दें यह पूरा मामला 26 जुलाई 2008 का है, जब अहमदाबाद में एक के बाद एक करीब 70 मिनट के अंदर कुल 21 बम ब्लॉस्ट हुए थे। इन धमाकों में 56 लोगों की जान चली गई थी और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। बम को साइकिल पर रखे टिफिन बॉक्स में छिपाया गया था। हमलावरों ने शहर की बसों, बाजारों और अस्पताल तक को निशाना बनाया था। धमाकों के बाद अहमदाबाद और सूरत से भी बम बरामद हुए थे। आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन ने इन धमाकों की जिम्मेदारी ली थी। बताया जाता है कि यह धमाके साल 2002 में हुए गुजरात दंगों का बदला लेने के लिए किए गए थे।

गौरतलब है कि साल 2008 की 26 जुलाई को 70 मिनट के बीच में 21 बम धमाकों से अहमदाबाद को हिलाकर रख दिया गया था। शहर के अलग-अलग हिस्सों में हुए इन धमाकों में 56 लोगों की जान गई थी, जबकि 200 लोग घायल हो गए थे। इन धमाकों की जांच अनेक साल चली और करीब 80 आरोपियों पर मुकदमा चलाया गया। इसके बाद अहमदाबाद की विशेष अदालत ने फरवरी 2022 में 38 लोगों को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई जबकि 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। अब गुजरात हाईकोर्ट ने उस फैसले को बरकरार रखा और सभी दोषियों की अपील खारिज कर दी है।

भारत ने जताई आपत्ति कहा- ये बिलकुल स्वीकार नहीं

बांग्लादेश की हिमाकत- जम्मू-कश्मीर को दिखाया पाक का हिस्सा

ढाका। भारत के अहसानों तले दबे बांग्लादेश की हिमाकत देखिए..कि उसने भारत का अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बता दिया। ढाका में आयोजित एक सेमिनार में भारत की क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती देते हुए एक ऐसा नक्शा प्रदर्शित किया, जिससे भारत का आक्रोशित होना स्वाभाविक था। राजधानी में एक रणनीतिक मामलों के सेमिनार के दौरान उस समय असहज स्थिति पैदा हो गई, जब प्रस्तुति में जम्मू-कश्मीर को पाकिस्तान का अभिन्न अंग दशार्या गया। भारत ने इस गंभीर उल्लंघन पर तत्काल और कड़ा विरोध दर्ज कराया। भारतीय उच्चायोग की एक अधिकारी ने कार्यक्रम के बीच में ही खड़े होकर स्पष्ट शब्दों में कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का एक अविभाज्य और अभिन्न अंग है, और इस प्रकार का कोई भी नक्शा पूरी तरह से भ्रामक और अस्वीकार्य है।

जैसे ही यह आपत्तिजनक नक्शा स्क्रीन पर आया, भारतीय उच्चायोग में सेकेंड सेक्रेटरी (पॉलिटिकल एंड इंफॉर्मेशन) पूजा कुमारी झा ने बिना किसी विलंब के अपनी आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने जोर देकर कहा कि यहां भारत का जो नक्शा प्रस्तुत किया गया है, वह तथ्यात्मक रूप से गलत है। पूजा कुमारी झा ने दोहराया कि जम्मू-कश्मीर भारत का एक अविभाज्य और मौलिक हिस्सा है, और इसलिए यह प्रस्तुति पूरी तरह से असत्य और अस्वीकार्य है। भारतीय अधिकारी की इस सशक्त आपत्ति के बाद, कार्यक्रम में मौजूद सभी प्रतिभागियों और गणमान्य व्यक्तियों का ध्यान तुरंत इस संवेदनशील मुद्दे की ओर गया। हालांकि, पूर्व राजदूत तारिक ए. करीम ने अपनी सफाई में कहा कि यह नक्शा केवल एक प्रतिनिधित्वात्मक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया गया था और इसका इरादा वास्तविक या आधिकारिक सीमाओं को दशार्ना नहीं था। इसके बावजूद, भारत ने उनके इस स्पष्टीकरण को स्वीकार करने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया और अपना विरोध दृढ़ता से दर्ज कराया। भारत का रुख इस संबंध में सदैव स्पष्ट रहा है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न और अविभाज्य हिस्से हैं।

वायनाड में भीषण भूस्खलन का भयावह दृश्य कैमरे में कैद, मृतकों की संख्या बढ़ी

टनल परियोजना स्थल पर हादसा, एनडीआरएफ और बचाव दल राहत कार्य में जुटे

वेब वार्ता, तिरुवनंतपुरम। केरल के वायनाड जिले में लगातार हो रही मूसलाधार वर्षा के बीच हुए भीषण भूस्खलन का भयावह दृश्य निगरानी कैमरे में कैद हुआ है। सामने आए दृश्य में तेज गति से बहते मलबे की चपेट में एक ईंधन टैंकर, बस और अन्य वाहन आ जाते हैं। घटना में कई लोगों के मलबे में दबने की आशंका है। प्रशासन के अनुसार मृतकों की संख्या बढ़ गई है, जबकि कई लोग अब भी लापता हैं। राहत एवं बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।

बताया जा रहा है कि यह हादसा वायनाड के कल्लाडी क्षेत्र में मीनाक्षी पुल के निकट सुरंग मार्ग निर्माण परियोजना स्थल पर हुआ। लगातार वर्षा के कारण पहाड़ी से भारी मात्रा में मिट्टी और मलबा अचानक नीचे आ गया, जिससे निर्माण स्थल और आसपास का क्षेत्र इसकी चपेट में आ गया। निगरानी कैमरे में कैद दृश्य में देखा जा सकता है कि मलबे का तेज बहाव एक भारी टैंकर को कई मीटर तक बहाकर ले जाता है और आसपास मौजूद लोग जान बचाने के लिए भागते दिखाई देते हैं।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पहले हल्की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद कुछ ही क्षणों में पूरा पहाड़ी हिस्सा खिसक गया। लोगों ने तुरंत आसपास मौजूद व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए चेताया, लेकिन तेज गति से आए मलबे ने निर्माण स्थल, बस स्टॉप और सड़क पर मौजूद कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है।

घटना में कई लोग घायल हुए हैं, जिनका विभिन्न अस्पतालों में उपचार चल रहा है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, पुलिस, अग्निशमन दल और अन्य एजेंसियां संयुक्त रूप से राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हैं। भारी मशीनों की सहायता से मलबा हटाकर लापता लोगों की तलाश की जा रही है, लेकिन लगातार वर्षा और क्षतिग्रस्त मार्गों के कारण अभियान प्रभावित हो रहा है।

बेकाबू कॉलेज बस ने घरों के बाहर खड़ी 5-6 गाड़ियों को मारी टक्कर

पंचकूला। पंचकूला के सेक्टर-26 में मंगलवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब एक निजी कॉलेज की बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे और घरों के बाहर खड़ी कई गाड़ियों से टकरा गई। इस जोरदार टक्कर में करीब 5 से 6 वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। सुबह-सुबह हुई इस दुर्घटना की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग सहम गए और तुरंत अपने घरों से बाहर निकल आए, जिसके बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के अनुसार, हादसे के तुरंत बाद बस चालक और स्थानीय निवासियों के बीच काफी देर तक तीखी नोकझोंक हुई।

संपादकीय

भारत का आर्थिक यथार्थ

मुद्रास्फीति और राजकोषीय घाटे को लेकर अलग-अलग आंकड़े और दावे हैं। बेशक आकलन भिन्न हैं, लेकिन सारांश यही है कि भारत आज विश्व की सबसे तेज और उभरती अर्थव्यवस्था है। भारत आज विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफवाद, विश्व व्यापार की बदलती और बिगड़ती व्यवस्था और अब भी जारी ईरान युद्ध के बावजूद वित्त वर्ष 2026 में भारत की आर्थिक विकास दर 7.7 फीसदी रही है। मुद्रास्फीति करीब 2 फीसदी है, जो पांच दशकों में सबसे कम है। चौतरफा संकटों के बावजूद चालू खाता घाटा जीडीपी का मात्र 0.6 फीसदी रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार जून में करीब 688 अरब डॉलर रहा, जो सशक्त अर्थव्यवस्था और निवेश का सूचक है। यह भंडार 700 अरब डॉलर से अधिक था, लेकिन ईरान युद्ध के कारण सप्लाई चेन बाधित हुई, कच्चे तेल के दाम बढ़े, लिहाजा हमारा आयात-बिल भी बढ़ गया, नतीजतन डॉलर के भंडार में कुछ कमी आई। विपरीत स्थितियों के बावजूद भारत का निर्यात (वस्तुएं और सेवाएं मिला कर) करीब 4 फीसदी बढ़ा है। यह अप्रैल-मई में करीब 15 फीसदी था। विदेशों में बसे और काम कर रहे प्रवासी भारतीय जो धन अपने माता-पिता, घरों को भेजते हैं, वह राशि करीब 140 अरब डॉलर है, जो सर्वकालिक अधिकतम है। यह भारतीय जीडीपी के 3.5-4 फीसदी के बराबर है।

किसी ने कहा कि भारत में जल्द ही आर्थिक सुनामी आने वाली है। कोई हमारी अर्थव्यवस्था के स्व-निर्मित आंकड़े गिनाता है और मृत अर्थव्यवस्था करार देने की कोशिश करता है। किसी अर्थशास्त्री का शोधात्मक अध्ययन है कि देश में 12 करोड़ से अधिक लोग ऐसे हैं, जो न तो पढ़ रहे हैं और न ही उनके पास कोई काम है।

क्या ऐसी अर्थव्यवस्था को संकटग्रस्त करार दे सकते हैं अथवा सुनामी के आंशिक संकेत भी मिल सकते हैं? हमारा राजकोषीय घाटा भी कम हुआ है। केंद्र सरकार का ऐसा घाटा जीडीपी के 4.4 फीसदी के समान है। बजट में भी यही लक्ष्य तय किया गया था। हालांकि राज्य सरकारों के साथ संयुक्त राजकोषीय घाटा 7.7 फीसदी के करीब है। यह घाटा भी बहुत ज्यादा है। यह 4 फीसदी से कम होना चाहिए। दरअसल यही भारतीय अर्थव्यवस्था का सारांश यथार्थ है, जो गुलाबी लगता है। कई संदर्भों में हरा भी प्रतीत होता है, जो गतिशीलता का प्रतीक है। बहरहाल अर्थव्यवस्था को लेकर कुछ सवाल किए जा सकते हैं। मसलन-औसत घरेलू मांग कम क्यों है? क्या देश के आम नागरिक की क्रय-शक्ति घटी या सीमित है? मांग का सीधा असर बाजार, उत्पादन, रोजगार पर पड़ता है। भारत में बेरोजगारी दर के बजाय रोजगार की दर एक अहम चिंतित सरोकार है। सरकारी एजेंसियां और संस्थाएं रोजगार की दर का खुलासा नहीं करतीं। बेरोजगारी दर आनुपातिक तौर पर कम हो जाती है। सरकारें उसी पर अपने गाल बजाने लगती हैं। सरकारी रपटों में ऐसे आकलन के दो मानदंड हैं। मार्च, 2026 में 15-59 साल आयु-वर्ग के 100 में से करीब 39 फीसदी लोगों के पास रोजगार था। करीब 10 साल पहले यही औसत करीब 43 फीसदी था। जाहिर है कि भारत में रोजगार घटे हैं। मान लीजिए कि देश में 15 साल से ऊपर की उम्र वाले 60 फीसदी लोग हैं। सरकारी भाषा में उन्हें कार्य-बल माना जाता है। यदि उनमें से औसतन 10 फीसदी पढ़ रहे हैं अथवा काम की तलाश में थक चुके हैं, तो श्रम-बल 50 फीसदी मान लिया जाता है। यदि श्रम-बल में 10 फीसदी बेरोजगार हैं, तो सरकार मानेगी कि 5 फीसदी लोग ऐसे हैं, जो काम की तलाश में हैं, लेकिन काम मिल नहीं पा रहा है। उस स्थिति में श्रम-बल 50 से घट कर 45 फीसदी हो जाएगा। बेरोजगारी दर शून्य मान ली जाएगी।

बिना वजह की लड़ाई का बेनतीजा अंत

कई यूरोपीय देशों ने युद्ध के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। हालांकि, कई अन्य देशों की सरकारें ईरान के खिलाफ अमरीका की आक्रमकता के बारे में बोलने से खुद को रोक रही थीं, लेकिन भारत सहित कई देशों के लोगों और मीडिया ने इस ह्यअन्यायपूर्णह्न युद्ध के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। कई खाड़ी देश, जिन्हें इस युद्ध के कारण नुकसान उठाना पड़ रहा था, सबसे ज्यादा चिंतित थे।

अब जब संयुक्त राज्य अमरीका-इजराइल और ईरान के बीच युद्ध एक समझौते (मेमोरैंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग) के साथ खत्म हो गया है, तो यह विश्लेषण करने का समय है कि इस युद्ध में किसे क्या मिला। हालांकि, जो देश युद्ध में शामिल नहीं होते, उन्हें दुनिया में युद्ध होना कभी पसंद नहीं आता, लेकिन इस बार अमरीका को दुनिया भर से अभूतपूर्व विरोध का सामना करना पड़ा है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत उत्साह के साथ ईरान पर हमला किया था और ईरान को दुनिया में शांति के लिए सबसे बड़ा खलनायक घोषित किया था, साथ ही इस हमले में इजराइल भी शामिल हो गया। यह पहली बार नहीं है जब अमरीका ने दूर-दराज के इलाकों में युद्ध की शुरूआत की हो। कई बार अमरीका विजेता बनकर उभरा और अपने घोषित लक्ष्यों को हासिल किया, लेकिन साथ ही कई बार उसे अपने लक्ष्य हासिल किए बिना ही पीछे हटना पड़ा और आलोचना का सामना करना पड़ा। हाल ही में अफगानिस्तान से अमरीका की वापसी इसी श्रेणी में आती है। 28 फरवरी, 2026 को शुरू हुए इस युद्ध में, ईरान ने शुरूआत में ही अपने सर्वोच्च नेता को खो दिया और उसे भारी जान-माल का नुकसान उठाना पड़ा, फिर भी ईरान ने न केवल हार मानने से इनकार किया, बल्कि अमरीका और इजराइल के खिलाफ जबरदस्त लड़ाई भी लड़ी। हालांकि इस युद्ध के लिए शायद ही दोनों पक्षों को कोई वैश्विक समर्थन मिला हो, लेकिन जैसे-जैसे युद्ध आगे बढ़ा, अमरीका तेजी से अपने समर्थकों को खोने लगा, जिसमें यूरोप के उसके पारंपरिक समर्थक भी शामिल थे। कई यूरोपीय देशों ने युद्ध के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। हालांकि, कई अन्य देशों की सरकारें ईरान के खिलाफ अमरीका की आक्रमकता के बारे में बोलने से खुद को रोक रही थीं, लेकिन भारत सहित कई देशों के लोगों और मीडिया ने इस ह्यअन्यायपूर्णह्न युद्ध के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। कई खाड़ी देश, जिन्हें इस युद्ध के कारण नुकसान उठाना पड़ रहा था, सबसे ज्यादा चिंतित थे। संघर्ष, अनिश्चितता, बाधित परिवहन और ग्लोबल वैल्यू चेन की आवाजाही, महंगाई आदि जैसे वैश्विक हालात दुनिया में ही नहीं, ट्रंप के घरेलू वोट बैंक पर भी असर डाल रहे थे, जिससे उन्हें युद्ध जारी रखने के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर होना पड़ा।

ट्रंप की शांति समझौते के लिए आतुरता- ईरान पर हमला करने के पीछे अमरीका का यह तर्क था कि ईरान एटमी हथियार बनाने की ओर अग्रसर हो रहा है, इसलिए उसे इस काम से रोकना होगा। ईरान को एटमी हथियारों से लैस होने से रोकने हेतु ईरान का 6 अन्य देशों के साथ संयुक्त व्यापक कार्य योजना का प्रयास 2015 में हुआ था, जिसे बाद में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के रूप में अनुमोदित भी कर दिया गया था और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र, अमरीका और यूरोप ने ईरान पर आण्विक संबंधी प्रतिबंध हटा दिए थे।

लेकिन वर्ष 2018 में अमरीका इस समझौते से बाहर हो गया और उसने ईरान पर दोबारा प्रतिबंध लगा दिया। बाद में ईरान के एटमी कार्यक्रमों के आगे बढ़ने के बाद संयुक्त राष्ट्र ने भी 2025 में ईरान पर प्रतिबंध लगा दिए थे। अमरीका का ईरान पर हमला उसे कमजोर करते हुए अपने एटमी कार्यक्रमों से रोकने के उद्देश्य से था। लेकिन ईरान ने इस संबंध में झुकने का रास्ता न चुनते हुए अमरीका के उन मित्र खाड़ी देशों, जिन्हें अमरीका ने सुरक्षा की गारंटी दे रखी थी, पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। जिन मुल्कों ने कभी इस प्रकार की स्थिति का सामना नहीं किया था, अब उन्हें अमरीका से दोस्ती के कारण बिना वजह नुकसान पहुंच रहा था। जब ईरान ने अपने प्रभाव क्षेत्र में आने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समुद्री यातायात पर रोक लगा दी, जिसके कारण भारत समेत कई देशों के लिए तेल का संकट खड़ा हो गया। ऐसे में अमरीका पर यह दबाव बना कि यदि उसे अपनी वैश्विक छवि को और अधिक धूमिल होने से बचाना है तो उसे युद्ध से बाहर आना ही होगा। दूसरे, चूंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इसलिए भी खोलना जरूरी हो गया, क्योंकि उसके कारण दुनिया भर में मुद्रा स्फीति का खतरा पैदा हो गया था, जिसका बड़ा असर अमरीका पर भी पड़ रहा था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना शांति वाताओं का प्रमुख उद्देश्य बन गया। तीसरे, डोनाल्ड ट्रंप को अपने देश अमरीका में भी भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा था। आम जनता का मानना था कि अमरीका ने बिना वजह ईरान के साथ युद्ध छेड़ कर अमरीकी अर्थव्यवस्था के लिए एक संकट तो खड़ा कर ही दिया है, आमजन को भी तेल की बढ़ी कीमतों के कारण भारी नुकसान पहुंच रहा है। अमरीका में मध्यावधि चुनाव नवंबर में होने वाले हैं, ऐसे में ट्रंप की गिरती साख इन चुनाव के नतीजों को प्रभावित कर सकती है। गौरतलब है कि अमरीकी हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव की सभी 435 सीटों और सैनेट की 100 में 35 सीटों के चुनाव इस बार दाव पर है। बड़ी संख्या में विभिन्न राज्यों के गर्वनरों के चुनाव भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। कुल मिलाकर ये चुनाव ट्रंप के लिए जनमत संग्रह माना जा रहा है। इसलिए ट्रंप के लिए जरूरी था कि इन मध्यावधि चुनावों के संबंध में उनके लिए माहौल न बिगड़े। चौथे, अमरीका को यह बात समझ में आ गई थी कि जिस प्रकार ईरान केवल हार मानने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि अमरीका की छवि को धूमिल करने का हर संभव प्रयास भी कर रहा था। ऐसे में ईरान के साथ एटमी समझौते हेतु वातावरण बनाने के लिए भी युद्ध को रोका जाना जरूरी था। पांचवें, ट्रंप स्वयं को शांति दूत के नाते स्थापित करने के लिए उत्सुक दिखाई दे रहे हैं और अपनी एक ऐसी छवि बनाना चाहते थे कि वे युद्ध के मुकाबले वार्ता से शांति स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन ट्रंप की किसी भी हालत में समझौता करने की उत्सुकता पूरी तरह से उजागर हो चुकी थी, जिसके चलते ईरान अपनी शर्तें मनवाने की स्थिति में आ गया था। अमरीका जैसी महाशक्ति के साथ शांति समझौते में ईरान अपनी शर्तें मनवाने में सफल रहा।

अमरीका और ईरान युद्ध खत्म करने और लंबे समय तक शांति बनाए रखने के लिए 14-सूत्रीय समझौते (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग) पर सहमत हो गए हैं। इस समझौते में दोनों देश युद्धविराम, संप्रभुता का सम्मान, होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलना और सुरक्षित व्यावसायिक नौवहन जैसे मुद्दों पर सहमत हो गए हैं। समझौते का एक मुख्य प्रावधान यह है कि अमरीका ईरान में युद्ध से हुई तबाही के बाद पुनर्निर्माण और बहाली के लिए लगभग 300 अरब डॉलर देने और धीरे-धीरे प्रतिबंध हटाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके बदले में, ईरान ने परमाणु हथियार न बनाने और अपने संवर्धित यूरेनियम को अंतरराष्ट्रीय निगरानी में रखने का वादा किया है। 60 दिनों के भीतर दोनों देश एक व्यापक समझौते हेतु सहमत हुए हैं। समझौते की शर्तें यह इंगित करती हैं कि ट्रंप को इस समझौते को करने के लिए काफी झुकना पड़ा। सोशल मीडिया में भी राष्ट्रपति ट्रंप की इस रणनीतिक कमजोरी को काफी प्रमुखता से स्थान मिला। शायद अमरीका के इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति को उतना विरोध नहीं झेलना पड़ा, जितना पिछले लगभग चार महीनों में ट्रंप को झेलना पड़ा है। सभी देश व्यक्तिगत या राष्ट्रीय अहंकार की लड़ाइयों में उलझने या दूसरे देशों को सैन्य और आर्थिक रूप से गुलाम बनाने की कोशिश करने के बजाय मिलकर इस धरती को रहने के लिए बेहतर जगह बनाएंगे और मानवता के सामने मौजूद असली समस्याओं जैसे पिछड़ापन, गरीबी, भुखमरी, पर्यावरण का नुकसान और ग्लोबल वार्मिंग,को हल करेंगे। शांति समझौते में भी, साढ़े तीन महीने की भीषण लड़ाई के बाद, सभी पक्ष देशों की संप्रभुता का सम्मान करने पर सहमत हुए हैं, तो क्यों न यह काम बिना युद्ध के ही किया जाए।

डा. अश्वनी महाजन, पूर्व प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय

साणंद का सेमीकंडक्टर केंद्र, आत्मनिर्भर भारत की नई पहचान

गुजरात के साणंद में सीजी सेमी की आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट (ओएसएटी) सुविधा का संचालन केवल एक औद्योगिक परियोजना नहीं, बल्कि भारत के तकनीकी भविष्य की दिशा तय करने वाला ऐतिहासिक कदम है। आज जब दुनिया की अर्थव्यवस्था सेमीकंडक्टर चिप्स पर निर्भर होती जा रही है, ऐसे समय में भारत का इस क्षेत्र में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता और आर्थिक सुरक्षा, दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चार जुलाई को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के साणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट (ओएसएटी) सुविधा का उद्घाटन कर देश को समर्पित किया।

ओएसएटी सुविधा का कार्य चिप निर्माण के बाद उनकी असेंबली, पैकेजिंग और परीक्षण करना होता है। यह सेमीकंडक्टर उद्योग की आपूर्ति श्रृंखला का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब तक भारत इस क्षेत्र में लगभग पूरी तरह विदेशी कंपनियों और आयातित चिप्स पर निर्भर रहा है, जिससे वैश्विक संकट या आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में देश के इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, दूरसंचार और रक्षा क्षेत्र प्रभावित होते रहे हैं। साणंद में स्थापित यह इकाई इस निर्भरता को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी।

करीब 7,600 करोड़ रुपये के निवेश से विकसित यह परियोजना भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में एक नई पहचान दिलाने की क्षमता रखती है। यह संयंत्र ऑटोमोबाइल, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, 5जी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) और ऊर्जा क्षेत्र के लिए चिप्स की पैकेजिंग और परीक्षण करेगा। इससे देश के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र को मजबूती मिलेगी तथा मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया अभियानों को नई गति प्राप्त होगी।

इस परियोजना का एक बड़ा लाभ रोजगार सृजन के रूप में सामने आएगा। उच्च तकनीक आधारित उद्योगों के विकास से इंजीनियरों, तकनीशियनों और शोधकताओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। इससे देश के युवाओं को अत्याधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त होगा, जो भारत को केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि प्रौद्योगिकी उत्पादक राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में सहायक बनेगा। आने वाले वर्षों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों रोजगार सृजित होने की संभावना है।

साणंद पहले ही ऑटोमोबाइल और विनिर्माण उद्योग का प्रमुख केंद्र रहा है। अब सेमीकंडक्टर उद्योग के आगमन से यह क्षेत्र भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में विकसित हो सकता है। यहां अन्य वैश्विक कंपनियों की उपस्थिति, निवेश और अनुसंधान गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे देश की औद्योगिक क्षमता में वृद्धि होगी।

वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर उद्योग रणनीतिक महत्व रखता है। कोविड महामारी और अंतरराष्ट्रीय तनावों के दौरान दुनिया ने चिप्स की कमी के दुष्प्रभावों को देखा है। ऐसे में भारत का अपना सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना आर्थिक ही नहीं, बल्कि सामरिक दृष्टि से भी आवश्यक है। साणंद का ओएसएटी केंद्र इस दिशा में भारत के आत्मविश्वास और दूरदर्शी नीति का प्रतीक है। निस्संदेह, गुजरात के साणंद में स्थापित सीजी सेमी ओएसएटी सुविधा भारत को तकनीकी आत्मनिर्भरता, रोजगार, निर्यात वृद्धि और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का माध्यम बनेगी। यह केवल एक उद्योग की शुरूआत नहीं, बल्कि विकसित भारत के उस स्वप्न की नींव है जिसमें देश विश्व की उन्नत तकनीकी शक्तियों की अग्रिम पंक्ति में खड़ा दिखाई देगा।

(लेखक - सौरभ वार्ष्णेय)
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार, चिंतक, राजनीतिक विचारक है।)
(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

हमीरपुर की जुडाक अंकिता ठाकुर ने स्वर्ण व शिवांश ने कांस्य पदक स्कूल नैशनल में जीतकर हिमाचल का मान बढ़ाया है। अन्य कुछ और खेलों में भी हिमाचल के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले कई वर्षों से राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को उनके द्वारा जीते गए पदकों के लिए सम्मान व ईनाम बांट समारोह आयोजित नहीं हो रहा था।

जींद से देश को मिलेगी पहली हाइड्रोजन ट्रेन

भारतीय रेलवे के इतिहास में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। भारत अब जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया, कनाडा, फ्रांस, स्वीडन के बाद हाइ्रोजन ट्रेन वाला आठवां देश बन जायेगा जिसका परीक्षण भी सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। हरियाणा के विकास को गति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 17 जुलाई को हरी झंडी दिखाकर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह केवल एक नई रेल सेवा की शुरूआत नहीं, बल्कि भारत के हरित भविष्य, ऊर्जा आत्मनिर्भरता और तकनीकी क्षमता का प्रतीक भी है।

हाइड्रोजन ट्रेन के संचालन के साथ भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा जिन्होंने स्वच्छ ईंधन आधारित रेल परिवहन को अपनाया है। जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया, कनाडा, फ्रांस और स्वीडन जैसे विकसित देशों के बाद भारत हाइड्रोजन ट्रेन तकनीक अपनाने वाला आठवां देश बनने जा रहा है। यह उपलब्धि भारत की बढ़ती तकनीकी दक्षता और नवाचार क्षमता को वैश्विक स्तर पर स्थापित करेगी।

हाइड्रोजन ट्रेन ऐसी रेलगाड़ी होती है जो डीजल के स्थान पर हाइड्रोजन ईंधन का उपयोग करती है। इसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक के माध्यम से बिजली उत्पन्न की जाती है, जिससे ट्रेन संचालित होती है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा उत्पादन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होता, बल्कि केवल जलवाष्प और पानी निकलता है। यही कारण है कि इसे पर्यावरण के अनुकूल और भविष्य की परिवहन प्रणाली माना जा रहा है। विश्व भर में बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करने के लिए हाइड्रोजन ऊर्जा को एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। भारतीय रेलवे भी वर्ष 2030 तक नेट-जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है, जिसमें हाइड्रोजन ट्रेनें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के कोच चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्टरी (आईसीएफ) में तैयार किए गए हैं। इस परियोजना का सफल परीक्षण भी पूरा हो चुका है, जिससे इसके सुरक्षित और प्रभावी संचालन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। रेलवे विशेषज्ञों के अनुसार हाइड्रोजन ट्रेन पारंपरिक डीजल ट्रेनों की तुलना में अधिक पर्यावरण-अनुकूल होने के साथ-साथ कम शोर उत्पन्न करती है। इसके संचालन से ईंधन आयात पर निर्भरता कम होगी और स्वदेशी तकनीक को भी बढ़ावा मिलेगा।

यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्रीन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

जींद से हाइड्रोजन ट्रेन के संचालन का निर्णय हरियाणा के लिए भी विशेष महत्व रखता है। इससे प्रदेश की औद्योगिक, आर्थिक और तकनीकी पहचान को नई मजबूती मिलेगी। रेलवे अवसंरचना के विकास से क्षेत्र में निवेश की संभावनाएँ बढ़ेंगी, रोजगार के अवसर सृजित होंगे तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।

हरियाणा पहले से ही ऑटोमोबाइल, विनिर्माण और कृषि क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में शामिल है। अब स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन प्रणाली के जुड़ने से राज्य आधुनिक तकनीक और हरित विकास का केंद्र बन सकता है। वर्तमान समय में प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया के लिए गंभीर चुनौती बने हुए हैं। परिवहन क्षेत्र कार्बन उत्सर्जन का एक बड़ा स्रोत है। ऐसे में हाइड्रोजन आधारित रेल सेवाएं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती हैं।

हाइड्रोजन ट्रेनें न केवल वायु प्रदूषण को कम करेंगी, बल्कि ध्वनि प्रदूषण में भी कमी लाएंगी। इनके व्यापक उपयोग से जीवाश्म ईंधनों की खपत घटेगी और ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी। हाइड्रोजन ट्रेन का सफल संचालन भारत की तकनीकी क्षमता और अनुसंधान कौशल का परिचायक है। आज भारत केवल प्रौद्योगिकी का उपभोक्ता नहीं, बल्कि नवाचार और आधुनिक समाधानों का निमार्ता भी बनकर उभर रहा है। सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष विज्ञान, डिजिटल प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निरंतर प्रगति के बाद हाइड्रोजन ट्रेन परियोजना भारत की उपलब्धियों में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ने जा रही है। यह पहल विश्व समुदाय को भी यह संदेश देती है कि भारत आर्थिक विकास के साथ-साथ पर्यावरणीय दायित्वों के प्रति भी समान रूप से प्रतिबद्ध है। जींद से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ भारतीय रेलवे के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज होगा। यह केवल एक रेल परियोजना नहीं, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा, तकनीकी आत्मनिर्भरता और सतत विकास के भारत के संकल्प का प्रतीक है। आने वाले समय में यदि हाइड्रोजन तकनीक का विस्तार व्यापक स्तर पर होता है, तो भारत न केवल परिवहन क्षेत्र में क्रांति ला सकेगा, बल्कि वैश्विक हरित अर्थव्यवस्था में भी अग्रणी भूमिका निभा सकेगा। 17 जुलाई का दिन भारतीय रेलवे और हरियाणा दोनों के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि का साक्षी बनने जा रहा है।

सौरभ वार्ष्णेय
लेखक वरिष्ठ पत्रकार, चिंतक, राजनीतिक विचारक है।

आसमान का कहर

लंबे इंतजार के बाद मानसून ने दिखाया रौद्र रूप, देशभर में जनजीवन अस्त-व्यस्त

लंबे इंतजार के बाद जब मानसून ने पूरे देश में दस्तक दी तो लोगों के चेहरों पर खुशी थी। भीषण गर्मी और पानी के संकट से जूझ रहे करोड़ों लोगों को उम्मीद थी कि बारिश राहत लेकर आएगी, खेतों में हरियाली लौटेगी और जलस्रोत भर जाएंगे। लेकिन इस बार मानसून ने राहत से ज्यादा आफत का रूप दिखाया। देश के अनेक राज्यों में मूसलाधार बारिश ने बाढ़, जलभराव, भूस्खलन और हादसों का ऐसा सिलसिला शुरू कर दिया कि जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया। कई स्थानों पर लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा, सैकड़ों गांवों का संपर्क टूट गया, सड़कें नदियों में बदल गईं और करोड़ों रुपये की संपत्ति पलभर में तबाह हो गई।

सबसे अधिक असर महाराष्ट्र में देखने को मिला। रायगढ़ जिले के जेनिथ वॉटरफॉल पर घूमने पहुंचे करीब 100 पर्यटक अचानक पानी का स्तर बढ़ जाने से बीच में फंस गए। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि प्रशासन को तत्काल राहत एवं बचाव दल भेजना पड़ा। रस्सियों की सहायता से सभी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। यह घटना बताती है कि मानसून के दौरान प्राकृतिक पर्यटन स्थलों पर थोड़ी-सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है। वहीं मुंबई महानगर और उसके आसपास के इलाकों में लगातार बारिश ने शहर की रफ्तार थाम दी। वसई और नालासोपारा की सड़कें नदी में तब्दील हो गईं, जहां लगभग 20 कारें पानी में डूब गईं। कई स्थानों पर वाहन बहने लगे। मुंबई में 64 पेड़ गिरने और आठ मकानों की दीवारें ढहने की घटनाएं सामने आईं। आरे कॉलोनी में पेड़ की टहनी गिरने से बाइक सवार 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जिसने बारिश के बीच सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए।

पुणे में लगातार बारिश के कारण एक रिहायशी सोसायटी की चहारदीवारी ढह गई, जिससे पार्किंग में खड़ी सात कारें और सात मोटरसाइकिलें मलबे में दब गईं। ठाणे में पाइपलाइन फटने से सड़कें जलमग्न हो गईं। जगह-जगह जलभराव के कारण लोगों को घंटों ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। रेल और सड़क यातायात भी प्रभावित हुआ। महानगर की पुरानी जल निकासी व्यवस्था एक बार फिर भारी बारिश के सामने बेबस नजर आई।

गुजरात में भी मानसून ने जमकर तबाही मचाई। जूनागढ़ में कई रिहायशी इलाकों में चार-चार फुट तक पानी भर गया। हालात ऐसे हो गए कि लोगों को नावों के सहारे सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। बच्चों को स्कूल जाने और लोगों को दैनिक कार्यों के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा। भावनगर में तेज बहाव में एक कार बह गई। अहमदाबाद सहित कई शहरों में सड़कें जलमग्न हो गईं और सामान्य जीवन प्रभावित हो गया। दुकानों, घरों और छोटे व्यवसायों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा।

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मात्र आधे घंटे की बारिश ने पूरे शहर की तस्वीर बदल दी। कई इलाकों में घरों के भीतर घुटनों तक पानी भर गया। टाटीबंध सहित अनेक कॉलोनियों में लोगों का घरेलू सामान खराब हो गया। बिजली व्यवस्था प्रभावित हुई और लोगों को रातभर परेशानी का सामना करना पड़ा। कई परिवारों को अपने घर छोड़कर रिश्तेदारों या सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। बारिश का पानी घरों में घुसने से छोटे बच्चों और बुजुर्गों को सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

मध्य प्रदेश में भी मानसून का असर बेहद गंभीर रहा। कई जिलों में नदियां उफान पर पहुंच गईं और पुलों के ऊपर से पानी बहने लगा। श्योपुर जिले में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि उसकी बेटी गंभीर रूप से झुलस गई। आष्टा क्षेत्र में डूबने से दो मासूम बच्चों की जान चली गई। हरदा जिले में नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि पुलों पर आवागमन रोकना पड़ा। कई गांवों का संपर्क मुख्य मार्गों से कट गया।

उत्तर प्रदेश में कानपुर सहित कई शहरों में सड़कें जलमग्न हो गईं। घुटनों तक पानी भरने से लोगों को आवागमन में भारी परेशानी हुई। वहीं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पूर्वोत्तर राज्यों में भी लगातार बारिश के कारण प्रशासन को अलर्ट जारी करना पड़ा। हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। जम्मू-कश्मीर में लगातार बारिश के चलते बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ, जिससे सड़कें बंद हो गईं और यातायात बाधित हो गया।

बारिश के कारण केवल जान-माल का नुकसान ही नहीं हुआ, बल्कि करोड़ों रुपये की सार्वजनिक और निजी संपत्ति भी बर्बाद हो गई। हजारों वाहन क्षतिग्रस्त हुए, मकानों की दीवारें ढह गईं, बिजली के खंभे गिर गए और पेड़ उखड़ने से कई इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई। किसानों की फसलें भी जलभराव से प्रभावित हुईं। जहां कुछ क्षेत्रों में पर्याप्त बारिश खेती के लिए वरदान साबित हो सकती है, वहीं अत्यधिक वर्षा खेतों में खड़ी फसलों को नष्ट कर देती है। ग्रामीण इलाकों में कच्चे मकानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा।

विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण अब बारिश का स्वरूप बदल रहा है। पहले जहां पूरे मौसम में संतुलित वर्षा होती थी, वहीं अब बहुत कम समय में अत्यधिक बारिश होने लगी है। शहरों में तेजी से बढ़ते कंक्रीट के जंगल, जल निकासी व्यवस्था की खामियां, नालों पर अतिक्रमण और प्राकृतिक जलमार्गों का अवरुद्ध होना स्थिति को और गंभीर बना देता है। यही कारण है कि कुछ घंटों की बारिश भी बड़े शहरों को ठप कर देती है।

मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी कई राज्यों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। कई स्थानों पर रेड और ऑरेंज अलर्ट घोषित किए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से नदियों, झरनों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने तथा मौसम संबंधी आधिकारिक चेतावनियों का पालन करने की अपील की है। राहत और बचाव दल लगातार संवेदनशील इलाकों में तैनात हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता पहुंचाई जा सके।

बारिश जीवन का आधार है और कृषि प्रधान भारत के लिए मानसून किसी वरदान से कम नहीं माना जाता। लेकिन जब यही बारिश संतुलन खो देती है तो वह विनाश का कारण बन जाती है। इस बार देश के अनेक राज्यों में मानसून ने यही संदेश दिया है कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए केवल राहत कार्य पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि मजबूत आधारभूत संरचना, प्रभावी जल निकासी व्यवस्था, समय पर चेतावनी प्रणाली और पर्यावरण संरक्षण पर गंभीरता से काम करना होगा। तभी बारिश राहत का प्रतीक बनेगी, आफत का नहीं।

(लेखक- कांतिलाल मांडोत)
(L 103 जलवन्त टाऊनशिप पूणा बॉम्बे मार्केट रोड, नियर नन्दालय हवेली सूरत मो 99749 40324 वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार-स्तम्भकार)

संक्षिप्त वार्ता

शादी के 72 दिन बाद आकृति की संदिग्ध मौत, पति गिरफ्तार

नई दिल्ली, 07 जुलाई (वेब वार्ता)। राजधानी दिल्ली में विवाह के मात्र 72 दिन बाद 28 वर्षीय आकृति सुतार की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोधी कॉलोनी क्षेत्र में एक इमारत से गिरने के बाद हुई मौत के मामले में पुलिस ने जांच के उपरांत पति अरस्तु सिक्का को गिरफ्तार कर लिया है। मामला दहेज प्रताड़ना और दहेज मृत्यु से जुड़े प्रावधानों के अंतर्गत दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार आकृति सुतार का विवाह 24 अप्रैल को अरस्तु सिक्का के साथ दोनों परिवारों की सहमति से हुआ था। दोनों लगभग दो वर्षों से एक-दूसरे को जानते थे। विवाह के कुछ ही सप्ताह बाद आकृति की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई, जिसके बाद परिजनों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए।

वजीराबाद रोड पर दिसंबर तक प्रभावित रहेगा यातायात

नई दिल्ली, 07 जुलाई (वेब वार्ता)। उत्तर पूर्वी दिल्ली में वजीराबाद रोड पर डबल डेकर फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के चलते भजनपुरा मेट्रो स्टेशन से ब्रजपुरी कट के बीच दोनों तरफ की सड़क पर दिसंबर तक यातायात प्रभावित रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर कहा है कि निर्माण स्थल पर लेन प्रतिबंध के कारण जाम मिल सकता है। खासतौर पर पीक आवर्स में ज्यादा परेशानी हो सकती है। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा पहले से योजनाबद्ध करें, पर्याप्त समय लेकर निकलें। गोकुलपुरी की ओर से आ रहे वाहन गोकलपुरी फ्लाईओवर, सीलमपुर होते हुए शास्त्री पार्क व उससे आगे जा सकते हैं। इसी तरह शास्त्री पार्क से गोकलपुरी जाने वाले सलीमपुर होते हुए जाएं। भजनपुरा के लोग यमुना कॉलोनी के अंदर के रास्तों से होते हुए पुश्ता रोड से शास्त्री पार्क की ओर जा सकते हैं। जिन्हें भजनपुरा से ब्रजपुरी जाना है, वह पुश्ता रोड से खजूरी होते हुए जा सकते हैं। पुलिस ने लोगों को लेन अनुशासन बनाए रखने की सलाह दी है। साथ ही वजीराबाद रोड पर वाहन न खड़ा करने की हिदायत दी है।

रंगदारी का आरोपी मुठभेड़ में घायल

नई दिल्ली, 07 जुलाई (वेब वार्ता)। मध्य जिला स्पेशल स्टाफ ने रंगदारी के लिए प्रापर्टी डीलर पर फायरिंग में आरोपी को सोमवार रात मुठभेड़ के बाद दबोच लिया। आईटीओ स्थित कब्रिस्तान के पास मुठभेड़ में आरोपी पवन कुमार के दोनों पैरों में गोली लगी है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस इस मामले में अब तक कुल पांच लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस के अनुसार, 29 जून को आर्यानगर स्थित अपने आफिस में प्रापर्टी डीलर राहुल जिंदल बैठे थे। इसी दौरान पवन कुमार नाम का बदमाश आया। उसने पिस्टल दिखाते हुए पीड़ित से 30 लाख रुपये की रंगदारी मांगी जिसमें से पांच लाख तुरंत देने को कहा। पीड़ित के मना करने पर हत्या की नीयत से फायरिंग की जिसमें वह बच गया।

मंगोलपुरी में दो भाइयों पर चाकू से हमला, एक की मौत

नई दिल्ली, 07 जुलाई (वेब वार्ता)। बाहरी दिल्ली के मंगोलपुरी क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते दो भाइयों पर चाकू से हमला कर दिया गया। इस घटना में महेश की मौत हो गई, जबकि उनके भाई मुकेश गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस के अनुसार, घटना की सूचना 6 जुलाई की रात लगभग 9:37 बजे मिली। इसके बाद पुलिस दल मौके पर पहुंचा। महेश को स्वजन तत्काल अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं मुकेश का उपचार जारी है।

एनडीएमसी ने 34 स्थानों पर शुरू किया व्यापक पौधारोपण अभियान

612 वृक्ष और 50,200 झाड़ियां लगाईं

नई दिल्ली, वेब वार्ता

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने राजधानी के हरित क्षेत्र को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को अपने क्षेत्र के 34 विभिन्न स्थानों पर 'व्यापक पौधारोपण अभियानझ2026' का शुभारंभ किया। यह अभियान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा प्रारंभ किए गए दिल्लीव्यापी पौधारोपण अभियान का हिस्सा है। अभियान के अंतर्गत एनडीएमसी क्षेत्र में 612 से अधिक वृक्षों तथा 50,200 झाड़ियों का रोपण किया गया।

इस अभियान में दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज, एनडीएमसी के अध्यक्ष केशव चंद्रा, उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल तथा परिषद के अन्य सदस्यों ने विभिन्न स्थानों पर पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, व्यापारिक संगठन, शैक्षणिक संस्थान, सामाजिक संगठन और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक भी शामिल हुए।

प्रवेश साहिब सिंह ने इंडिया गेट स्थित चिल्ड्रन्स पार्क में पौधारोपण किया, जबकि बांसुरी स्वराज ने लक्ष्मीबाई नगर स्थित संजय झील पार्क में पौधा लगाया। एनडीएमसी अध्यक्ष केशव चंद्रा ने नेहरू पार्क, उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने लोधी गार्डन, सदस्य अनिल वाल्मीकि ने तालकटोरा गार्डन, सदस्य डी.पी. सिंह ने कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क तथा सदस्य सरिता तोमर ने लोधी रोड स्थित वीर सावरकर पार्क में पौधारोपण अभियान का नेतृत्व किया।

एनडीएमसी के अनुसार अभियान के लिए 50,200 से अधिक पौधारोपण गड्ढे पहले से वैज्ञानिक ढंग से तैयार किए गए थे। निर्धारित लक्ष्य से अधिक सफलता प्राप्त करते हुए परिषद ने विभिन्न हरित क्षेत्रों में 612 से अधिक वृक्ष और 50,200 झाड़ियों का रोपण किया।

अभियान के दौरान पीपल, नीम, जामुन, इमली, चंपा, अशोक, गुलमोहर और अमलतास जैसी देशी वृक्ष प्रजातियों के साथ-साथ हामेलिया, जस्टिसिया, कैना, लिली, मुराया सहित विभिन्न सजावटी एवं जैव विविधता को बढ़ावा देने वाली झाड़ियों का रोपण किया गया। एनडीएमसी का उद्देश्य हरित क्षेत्र का विस्तार करने के साथ-साथ शहरी जैव विविधता को समृद्ध करना, वायु गुणवत्ता में सुधार लाना तथा सार्वजनिक स्थलों को अधिक पर्यावरण-अनुकूल बनाना है। परिषद ने बताया कि वर्तमान में वह लगभग 1,450 एकड़ हरित क्षेत्र का रखरखाव कर रही है। इसके अंतर्गत 6 प्रमुख पार्क, 122 कॉलोनी पार्क, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुरक्षित 981 पार्क, 52 विद्यालयों के हरित क्षेत्र, 51 गोलचक्कर, 14 बाजार उद्यान तथा लगभग 15,000 सड़क किनारे लगे वृक्ष शामिल हैं।

एनडीएमसी के अनुसार उसका क्षेत्र दिल्ली के कुल भौगोलिक क्षेत्र का केवल लगभग 3 प्रतिशत है, लेकिन राजधानी के कुल हरित आवरण में उसका योगदान लगभग 55 प्रतिशत है। परिषद का कहना है कि 'व्यापक पौधारोपण अभियानझ2026' पर्यावरण संरक्षण, जलवायु अनुकूलन और सतत शहरी विकास के प्रति उसकी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता का महत्वपूर्ण हिस्सा है तथा जनभागीदारी के माध्यम से स्वच्छ, स्वस्थ और हरित राजधानी के निर्माण का प्रयास निरंतर जारी रहेगा।

चार वर्षों में 6300 हेक्टेयर हरित क्षेत्र को बनाएंगे वन क्षेत्रः अमित शाह

नई दिल्ली, वेब वार्ता

दिल्ली में अगले चार वर्षों के भीतर 6,300 हेक्टेयर हरित रिज क्षेत्र को पूर्ण रूप से वन क्षेत्र में विकसित कर उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। यह 6,300 हेक्टेयर हरित रिज फेफड़े बनकर राजधानी के पर्यावरण की रक्षा करेगी। यह जानकारी केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को दिल्ली में शुरू किए गए पौधारोपण अभियान (एक पेड़ मां के नाम) को लेकर आयोजित कार्यक्रम में दी। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक देशी पौधे, 65 लाख से अधिक बड़े वृक्ष तथा 65 लाख अन्य पौधे लगाए जाएंगे। वहीं दिल्ली सरकार द्वारा 70 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है।

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली सरकार ने भारत सरकार की मदद से वर्किंग प्लान डॉक्यूमेंट (2026 से 2036) तैयार किया है। इसके माध्यम से असोला भाटी अभयारण्य प्रबंधन योजना और बायो-डायवर्सिटी एटलस पूरे ग्रीन ईको-सिस्टम को पुनर्जीवित करने का व्यापक प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार और दिल्ली सरकार का संकल्प है कि आने वाले चार वर्षों में रिज के अंदर 70 से अधिक तालाब और छोटे-छोटे रेस्टोरेंट बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हम रिज क्षेत्र में आठ विशेष वन लगाएंगे — नक्षत्र वन, मेल वन, ऋषि वन, तीर्थंकर वन, शंकर वन, वामन वृक्ष वन और पुरानी वाटिका। इनके माध्यम से हम लोगों को प्रकृति से जोड़ने का प्रयास करेंगे।

गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहन

(ईवी) नीति लाई है। यमुना शुद्धिकरण, रिज क्षेत्र का समग्र परिवर्तन, पर्यावरणीय इकोसिस्टम की बहाली और ईवी पॉलिसी - इन सभी प्रयासों के जरिए हम हरित दिल्ली की संकल्पना को साकार करेंगे। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान के तहत मंगलवार को केन्द्रीय रिज एवं नानकपुरा रिज में वृक्षारोपण कर दिल्ली रिज के पुनर्जीवन अभियान की शुरूआत की। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने नरेला में हाई-सिक्योरिटी जेल का शिलान्यास, स्वचालित वाहन परीक्षण केंद्र का लोकार्पण, तीन नए डिपो का उद्घाटन और 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ भी किया।

उन्होंने कहा कि वर्षों से दिल्ली रिज में पर्यावरण के अनुकूल नहीं होने वाले विदेशी और जहरीले बबूल जैसे वृक्षों ने जगह बना ली थी, अब इन्हें हटाकर देशी प्रजातियों के वृक्ष लगाए जाएंगे। दिल्ली के रिज को अगले तीन वर्षों में पीपल, बरगद, नीम, अर्जुन, जामुन जैसे 100 वर्ष से अधिक आयु वाले देशी वृक्ष लगाकर, इसे दिल्ली का फेफड़ा बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1994 में अधिसूचित दिल्ली रिज की अंतिम अधिसूचना 30 वर्षों तक लंबित थी, दिल्ली सरकार ने 5,000 हेक्टेयर रिज क्षेत्र को वन क्षेत्र घोषित कर कानूनी संरक्षण देने का काम किया है।

यमुना में नहीं जाएगा एक भी किलो गोबर

अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यमुना नदी के शुद्धिकरण के लिए जो लक्ष्य दिया है, उसे पूरा करने के लिए हम तेजी से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की डेयरियों का गोबर अब सीधे यमुना नदी में नहीं जाएगा। हम जल्दी ही राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के साथ समझौता करके यह व्यवस्था करेंगे कि एक किलो गोबर भी यमुना में न जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली की पिछली सरकार ने प्रतिदिन 1,500 मीट्रिक टन गोबर यमुना नदी में डालने का काम किया था।

त्रिलोकपुरी में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण, संजय झील में लगाए गए पौधे

नई दिल्ली, 07 जुलाई (वेब वार्ता)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ह्यएक पेड़ माँ के नामह्ल अभियान तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 70 लाख पौधारोपण संकल्प के तहत मंगलवार को त्रिलोकपुरी विधानसभा के 13 ब्लॉक स्थित संजय झील परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्र में हरित आवरण बढ़ाना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनजागरूकता को प्रोत्साहित करना रहा।

इस अवसर पर त्रिलोकपुरी विधानसभा के विधायक रविकांत ने कहा कि प्रकृति का संरक्षण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक पौधे लगाकर और उनकी नियमित

देखभाल सुनिश्चित कर ही स्वच्छ, हरित और प्रदूषण मुक्त वातावरण का निर्माण किया जा सकता है। उन्होंने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण के लिए जनभागीदारी बढ़ाने का आह्वान भी किया। कार्यक्रम में उप मंडलाधिकारी, पटपड़गंज डॉ. नितिन सांक्या, विधानसभा प्रभारी सुनील गुप्ता, उत्तराखंड प्रकोष्ठ के संयोजक दिग्पाल कैंतुरा, राज अग्रवाल तथा अंजनी आर्यन सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। पौधारोपण अभियान में क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिकों, सामाजिक कार्यकताओं, सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों तथा विद्यालयों के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। उपस्थित लोगों ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेते हुए लगाए गए पौधों की देखभाल का भी भरोसा दिलाया। आयोजकों ने बताया कि इस प्रकार के अभियान न केवल हरित क्षेत्र बढ़ाने में सहायक होंगे, बल्कि लोगों में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी और जागरूकता भी विकसित करेंगे।

पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर भाजपा जनता को राहत देः सुभाष चंद्र लाला

नई दिल्ली, 07 जुलाई (वेब वार्ता)। आम आदमी पार्टी के विश्वास नगर वार्ड अध्यक्ष सुभाष चंद्र लाला ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद आम लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी महंगाई पर नियंत्रण करने में विफल रही है। सुभाष चंद्र लाला ने कहा कि यदि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की संभावना है तो आम जनता को इसका लाभ तुरंत मिलना चाहिए। उनका कहना था कि ईंधन की ऊंची कीमतों का सीधा असर परिवहन, फल-सब्जियों तथा दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतों पर पड़ता है, जिससे आम लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ता है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के पास महंगाई से निपटने के लिए प्रभावी नीति और ठोस योजना का अभाव है। उनका कहना था कि मध्य पूर्व में तनाव के दौरान भी महंगाई लगातार बढ़ी और पेट्रोल, डीजल तथा सीएनजी की कीमतों में कई बार वृद्धि हुई, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ीं। सुभाष चंद्र लाला ने कहा कि अब जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है, तब केंद्र सरकार को पेट्रोल और डीजल के दाम घटाकर आम जनता को राहत देनी चाहिए।

ऑपरेशन विश्वासः पुलिस ने छह माह में 2400 खोए और चोरी हुए मोबाइल बरामद किए, कीमत ढाई करोड़ रुपये से अधिक

नई दिल्ली, वेब वार्ता

दक्षिण-पश्चिम जिला पुलिस ने 'ऑपरेशन विश्वास' के तहते वर्ष 2026 के पहले छह महीनों (1 जनवरी से 30 जून) के दौरान 2400 खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को सौंपे हैं। बरामद मोबाइल फोन की अनुमानित कीमत 2.5 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है।

दक्षिण पश्चिम जिले के पुलिस उपायुक्त अमित गोयल ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि केवल 1 अप्रैल से 30 जून 2026 के बीच ही जिले में 1790 मोबाइल फोन बरामद

किए गए। इन मोबाइलों को तकनीकी जांच, डिजिटल ट्रैकिंग, फील्ड वेरिफिकेशन और विभिन्न राज्यों की पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर खोजा गया। इसके बाद जिले के सभी थाना क्षेत्रों में मोबाइल हैंडओवर कार्यक्रम आयोजित कर 1900 बरामद मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को लौटाए गए। लंबे समय बाद अपना मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने दिल्ली पुलिस के प्रयासों की सराहना की।

पुलिस उपायुक्त के अनुसार इस अभियान को सफल बनाने के लिए दक्षिण-पश्चिम जिले की एंटी स्नैचिंग सेल ने विशेष रिकवरी अभियान चलाया। यह अभियान इंस्पेक्टर हरि सिंह के नेतृत्व में संचालित किया गया। टीम में एसआई कमल कांत, एएसआई होशियार सिंह, एएसआई वीरेंद्र कुमार सहित कई पुलिसकर्मी और जिले के सभी थानों का स्टाफ शामिल रहा। वहीं आंकड़ों के अनुसार, जनवरी से जून 2026 के बीच बरामद किए गए 2400 मोबाइल फोन में से 1236 मोबाइल एंटी स्नैचिंग सेल ने, जबकि 1164 मोबाइल विभिन्न थाना पुलिस टीमों ने बरामद किए। सभी मोबाइल की कुल अनुमानित कीमत ढाई करोड़ रुपये से अधिक है।

पुलिस उपायुक्त ने बताया कि ऑपरेशन विश्वास का उद्देश्य केवल खोए या चोरी हुए मोबाइल बरामद करना नहीं, बल्कि लोगों का पुलिस पर विश्वास और मजबूत करना है। आधुनिक तकनीक, डिजिटल ट्रैकिंग, तकनीकी निगरानी और लगातार जांच के जरिए पुलिस खोए हुए मोबाइल तलाशकर उनके वास्तविक मालिकों तक पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि आगे भी यह अभियान जारी रहेगा।

त्रिलोकपुरी में भजन संध्या एवं विकसित भारत संकल्प सम्मेलन आयोजित, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली, 07 जुलाई (वेब वार्ता)। त्रिलोकपुरी विधानसभा के मयूर विहार स्थित श्री राम मंदिर में मंगलवार को ₹भजन संध्या एवं विकसित भारत संकल्प सम्मेलन₹ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भक्ति, सामाजिक सहभागिता और विकसित भारत के संकल्प पर आधारित विचारों का संगम देखने को मिला। इस अवसर पर भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

कार्यक्रम में त्रिलोकपुरी विधानसभा के विधायक रविकांत ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए सेवा, सुशासन और जनभागीदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भक्ति और विकास, दोनों नए भारत की पहचान बन चुके हैं तथा समाज के सभी वर्गों को राष्ट्र निर्माण के

संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए।

सम्मेलन में केंद्रीय राज्य मंत्री एवं दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण से जुड़े कार्यों पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए जनसहभागिता को महत्वपूर्ण बताया। इस अवसर पर प्रदेश मंत्री विनोद बछेती, जिला अध्यक्ष विजेंद्र धामा, जिला महामंत्री नीरज शर्मा, भावना जैन, विधानसभा प्रभारी सुनील गुप्ता, विधानसभा संयोजक जितेंद्र देधा, जिला उपाध्यक्ष विशाल कुमार, अधिवक्ता मोहित शर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष दर्शन पाल, राम चरण गुजराती, पूर्व विधायक रोहित मेहरोलिया, निगम पार्षद संजीव सिंह, पूर्व उपाध्यक्ष किसान मोर्चा अनुप चौधरी, मंडल अध्यक्ष सुनील कुमार सुंदर, राहुल सिंह, भीष्म तोमर तथा विभिन्न आवासीय कल्याण संघों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

तेज हवा संग दिल्ली से नोएडा, गाजियाबाद तक झमाझम बरसे बदरा

दिन में ही छाया अंधेरा

नई दिल्ली, 07 जुलाई (वेब वार्ता)। दिल्ली एनसीआर में मंगलवार को कई इलाकों में झमाझम बारिश देखने को मिली। पिछले गई दिनों से लोगों को उमर भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा था। मंगलवार को दोपहर में बारिश से मौसम पूरी तरह से बदल गया। नोएडा, गाजियाबाद समेत दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश ने मौसम सुहावना कर दिया। आसमान में काले बादलों से दिन में ही अंधेरा छा गया। दिल्ली में मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था।

मौसम विभाग ने दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई थी। इस पूवार्नुमान के अनुसार, दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर के लोनी देहात, हिंडन एएफ स्टेशन, गाजियाबाद, इंदिरापुरम, छपरौला, नोएडा, दादरी, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद और बल्लभगढ़ जैसे इलाकों में भी बारिश की उम्मीद थी।

नोएडा में बारिश ने दी गर्मी से राहत, तीन डिग्री लुढ़का तापमान

मंगलवार दोपहर हुई झमाझम बारिश से नोएडा में लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। सुबह जहां अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, वहीं बारिश के बाद तापमान गिरकर करीब 34 डिग्री सेल्सियस रह गया। मौसम में अचानक आए बदलाव से वातावरण सुहावना हो गया और कई इलाकों में लोगों ने राहत की सांस ली। नोएडा के सेक्टर-50, 16, 15, 18, 62, 74 और 75 समेत कई क्षेत्रों में तेज बारिश हुई। कुछ स्थानों पर सड़कों पर पानी भरने से वाहनों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। हालांकि बारिश के कारण गर्म हवाओं और उमस से काफी राहत मिली। कई लोग घरों और कार्यालयों से निकलकर मौसम का आनंद लेते नजर आए।

दिल्ली में सोमवार को ऐसा रहा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 38.6 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री दर्ज हुआ। इसके अलावा, अधिकतम 98 और न्यूनतम आर्द्रता 55 फीसदी दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 24-27 और अधिकतम तापमान 36-39 डिग्री सेल्सियस के दायरे में रहा।

केजरीवाल ने इथेनॉल-मिश्रित ईंधन को लागू करने के खिलाफ केंद्र सरकार पर साधा निशाना

नई दिल्ली, 07 जुलाई (वेब वार्ता)। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार देश पर इथेनॉल-मिश्रित ईंधन को जबरन थोप रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 6 बड़ी ऑटो कंपनियों पर इथेनॉल 20 को सुरक्षित बताने के लिए पत्रकार वार्ता करने का दबाव बनाया गया।

आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार लोगों के विरोध के बावजूद इथेनॉल 20 पेट्रोल थोप रही है और इसके लिए झूठ बोल रही है। उन्होंने कहा कि देश के करोड़ों वाहन मालिकों के विरोध के बावजूद पूरे देश पर जबरदस्ती ई20 पेट्रोल थोपी जा रही है। केजरीवाल ने कहा कि 3 जुलाई को सरकार ने 6 बड़ी ऑटो कंपनियों पर इथेनॉल20 को सुरक्षित बताने के लिए पत्रकार वार्ता करने का दबाव बनाया। तीन कंपनियों ने ऐसा दावा करने से साफ इनकार कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि मारुति सुजुकी, टोयोटा किर्लोस्कर और हीरो मोटोकॉर्प ने कहा कि पुरानी गाड़ियों में भी ई20 सुरक्षित है और इससे सिर्फ 5झ7 प्रतिशत माइलेज घटेगा।

उन्होंने कहा कि टोयोटा के आधिकारिक ओनर मैनुअल में केवल इथेनॉल 10 (10 प्रतिशत ई) तक के इस्तेमाल की अनुमति है। मैनुअल में यह भी

लिखा है कि ई10 से भी परफॉर्मेंस या माइलेज प्रभावित हो, तो इथेनॉल मुक्त (0 प्रतिशत) पेट्रोल पर वापस लौट जाएं। केजरीवाल ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब कंपनियों के आधिकारिक ओनर मैनुअल कह रहे हैं कि 10 प्रतिशत से ज्यादा इथेनॉल गाड़ियों को तबाह कर देगा, तो सरकार का 20 इथेनॉल को सुरक्षित बताना ग्राहकों के साथ सरासर धोखा है। उन्होंने कहा कि जब कंपनियों के अपने दस्तावेज इथेनॉल 10 की सीमा तय करते हैं, तो पत्रकार वार्ता में इथेनॉल 20 को पूरी तरह सुरक्षित कैसे बताया जा रहा है?

केजरीवाल ने सरकारी पत्रकार वार्ता में आई सभी ऑटो कम्पनियों को चिट्ठी लिखने की बात की। उन्होंने सभी कम्पनियों से कहा कि लिखित में वे अपने ग्राहकों को आश्वासन दें की गाड़ी में ई20 इस्तेमाल करने पर यदि माइलेज 10 प्रतिशत से ज्यादा गिरता है, तो कंपनी उसकी भरपाई करेगी और गाड़ी का कोई भी पार्ट डैमेज होता है, तो कंपनी उसे मुफ़्त में रिप्लेस करेगी। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने की बात की। उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री से पूछेंगे कि अगर किसी की गाड़ी में कोई भी दिक्कत आती है, तो उसका हरजाना कौन देगा? साथ ही केजरीवाल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार इथेनॉल पर दूसरे देशों का उदाहरण देकर लोगों के विरोध को दबाने की कोशिश कर रही है। जबकि जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका में ई10 से ऊपर का फ्यूल इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने प्रतापगढ़ में 384 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 111 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण/शिलान्यास

बाबरी ढांचे की जगह राममंदिर देखकर सपा व कांग्रेस को पीड़ा: सीएम योगी

प्रतापगढ़, वेब वार्ता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी व कांग्रेस के नेताओं को खरी-खरी सुनाते हुए राम मंदिर व वक्फ के मुद्दे पर आईना दिखाया। उन्होंने दो-टूक कहा कि हिंदू आस्था पर प्रहार करने वालों के मुंह पर वक्फ के नाम पर फेविकोल क्यों चिपक जाता है? दरअसल सपा व कांग्रेस की पीड़ा यह है कि वे जहां गुलामी का बाबरी ढांचा देखना चाहते थे, वहां भगवान राम का मंदिर बन गया है। सपाइयों व कांग्रेसियों को देख गिरगिट भी शर्मार्ता है कि यह प्रजाति हमसे भी तेज गति से रंग बदलती है।

मुख्यमंत्री ने मंगलवार को राजकीय इंटर कॉलेज में प्रतापगढ़ व विश्वनाथ गंज विधानसभा क्षेत्रों के लिए 384 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 111 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास किया। सीएम ने देवी-देवताओं, संतों, साहित्यकारों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, राजनेताओं का उल्लेख कर प्रतापगढ़ की समृद्ध विरासत को नमन किया। उन्होंने कहा कि आंवले की औषधीय मिठास बिखेर रहा प्रतापगढ़ स्वावलंबन का उदाहरण है। लेकिन प्रतापगढ़ के किसानों, बागवानों व उनके पूर्वजों ने आंवला उत्पादन कर हमें अमृत फल दिया।

अब कांग्रेस व सपा के चंगुल में नहीं फंसेगा देश, विपक्ष के दुष्प्रचार के बावजूद बड़ी संख्या में अयोध्या आ रहे श्रद्धालु

जातीय आधार पर समाज को बांटना चाहता है विपक्ष

सीएम ने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि आपने सपा व कांग्रेस समेत अन्य दलों के दलदल को देखा है। जिन्होंने युवाओं व नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, चुनाव आते ही वे फिर से साजिशें कर रहे हैं। विपक्ष को यूपी की प्रगति, उपद्रव से मुक्ति, उत्साहपूर्ण वातावरण, विरासत का सम्मान, मां बेल्हा देवी, मां चंद्रिका देवी, करपात्री जी महाराज के पुनरुद्धार कार्य और नौजवानों को रोजगार देना अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि नौजवान काम करेंगे तो जातिवाद की राजनीति समाप्त होगी। विपक्ष फिर से जातीय आधार पर समाज का ताना-बाना छिन्न-भिन्न करना चाहता है।

कांग्रेस व सपा को अयोध्या पर बोलने का अधिकार नहीं

सीएम ने कहा कि सपा व कांग्रेस के पास कोई नया मुद्दा नहीं है। इनके पास दो ही मुद्दे बचे हैं, जाति के नाम पर विभाजन और आस्था पर प्रहार। कुछ दिनों से ये लोग भारत की सनातन आस्था पर प्रहार करने की शरारत कर रहे हैं। अयोध्या में बाबरी ढांचे का समर्थन करने वाली कांग्रेस व सपा ने गिरगिट की तरह रंग बदला है। ये लोग कह रहे कि अयोध्या में आस्था से खिलवाड़ हो रहा है। आखिर अयोध्या पर इनकी आस्था कब से हो गई? रामभक्तों के पूर्वजों ने अयोध्या की लड़ाई लड़ी है, वे बोल सकते हैं, लेकिन कांग्रेस व सपा को अयोध्या पर बोलने का अधिकार नहीं है।

देश अब कांग्रेस व सपा के चंगुल में नहीं फंसेगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि राम के अस्तित्व पर प्रहार करने वाली कांग्रेस और रामभक्तों पर लाठी-गोली चलाने वाली समाजवादी पार्टी के मुंह से आस्था की बात अच्छी नहीं लग रही। हिंदू विरासत से जुड़े धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार का पैसा सपा कब्रिस्तान की बाउंड्रीवाल पर खर्च करती थी। अब यह देश कांग्रेस व सपा के चंगुल में नहीं फंसने वाला। आज की अयोध्या पीएम मोदी के विजन के अनुरूप प्रभु राम के समय का स्मरण कराती है। वहां फोरलेन, रेल, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट आदि की सुविधाएं केवल भाजपा ही कर सकती है। निषादराज रैनबसेरा, मां शबरी भोजनालय का निर्माण हुआ। राम की पैड़ी पर भव्य सुंदरता है। विपक्ष के दुष्प्रचार के बावजूद भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में अयोध्या आ रहे हैं।

वक्फ के नाम पर कांग्रेस-सपा के मुंह पर क्यों चिपका है फेविकोल

सीएम ने कहा कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्रदेश सरकार से एसआईटी के गठन की मांग की थी। मैंने कहा था कि एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी करके ही रहेगी। इसकी प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करते हुए ट्रस्ट ने एफआईआर दर्ज कराई। जिनके खिलाफ साक्ष्य थे, उन पर कार्रवाई भी हुई, लेकिन वक्फ के नाम पर कांग्रेस-सपा के मुंह पर फेविकोल क्यों चिपका है? ये लोग जब गोमाता की तस्करी कराते थे, अवैध स्लाटर हाउस में उसकी हत्या कराते थे, अयोध्या में लाठी-गोली चलाते थे, भगवान राम-कृष्ण को काल्पनिक कहते थे, कांवड़ यात्रा व दुर्गा पूजा के पंडालों को रोकते थे, त्योहारों के पहले दंगे कराते थे तब हिंदुओं की आस्था आहत नहीं होती थी? सपा व कांग्रेस वाले क्या इसका जवाब देंगे? हर जागरूक नागरिक को इन लोगों से ये प्रश्न करने चाहिए।

एक घटना को लेकर हिंदुओं को अपमानित कर रहे ये लोग

सीएम ने कहा कि सपा व कांग्रेस के लोग एक घटना को लेकर हिंदुओं को अपमानित कर आस्था पर प्रहार कर रहे हैं। अयोध्या में कथित चोरी पर हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन देश-प्रदेश में वक्फ के नाम पर गरीबों, कमजोर लोगों की हजारों हेक्टेयर लैंड बेची गई। इन जमीनों पर गरीबों को पट्टे दिए जा सकते थे। कन्वेंशन सेंटर, दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बनाए जा सकते थे। वक्फ के नाम पर कब्जा करा के और उसे बेचकर कुछ चुनिंदा लोगों ने हेरा-फेरी की है, लेकिन इस पर कांग्रेस व सपा ने एक शब्द नहीं बोला।

नौजवानों की नौकरी पर डकैती डालकर नीलामी करता था सैफई घराना

सीएम ने कहा कि अब प्रतापगढ़ के युवा भी नियुक्ति पत्र पाते हैं। 60,244 पुलिस भर्ती में यहां के भी सैकड़ों युवा भर्ती हुए। उप्र लोकसेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, शिक्षा चयन आयोग के परीक्षा परिणाम में भी यहां के युवा स्थान प्राप्त करते हैं। पहले सैफई घराना नौजवानों की नौकरी पर डकैती डालकर इनकी नीलामी करता था, जिससे होनहार नौकरियों से वंचित रहते थे। जब नौजवान पलायन करेगा तो दुर्गति तय है और यूपी इसीलिए बीमारू हुआ था। अब भी वही तंत्र, वही लोग, वही राज्य है, लेकिन एनडीए सरकार ने काम करने की स्टाइल बदली है। सीएम ने सरकार के विकास कार्यों को धरातल पर उतारने के लिए विधायकों के कार्यों की सराहना की। कहा, 2017 के पहले यहां मेडिकल कॉलेज कल्पना थी, लेकिन अब डॉ. सोनेलाल पटेल के नाम पर मेडिकल कॉलेज है। आज नर्सिंग कॉलेज का शिलान्यास हो रहा है, बेटियां इस मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग की पढ़ाई करेंगी। सीएम ने प्रगति को समृधि का आधार बताते हुए कहा कि मां बेल्हा देवी, चंद्रिका देवी मंदिर के सौंदर्यीकरण, करपात्री जी महाराज से जुड़े स्थल के कार्यों, कनेक्टिविटी के लिए प्रतापगढ़ को बेहतर अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए प्रयागराज व पश्चिमी यूपी से प्रतापगढ़ की दूरी कम की गई। सीएम ने कहा कि 9-10 वर्ष पहले प्रतापगढ़ की गिनती पिछड़े जनपदों में होती थी। यहां कनेक्टिविटी, सड़कों समेत बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। हर कोई हतोत्साहित था, पर अब सरकार का प्रोत्साहन पाने से हर कोई उत्साहित है। 2014 के पहले देश और 2017 के पहले प्रदेश में प्रोत्साहन का अभाव था, जिससे गरीब हताश और निराश था। नौजवान पलायन के लिए और किसान आत्महत्या के लिए विवश था। बेटी-बहन असुरक्षित, कारीगर बेरोजगार था। आशा की किरण नहीं दिख रही थी। पिछली सरकारों ने एक जनपद-एक माफिया दिया, हमने एक जनपद-एक मेडिकल कॉलेज दिया। वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट देकर हमने परंपरागत उद्यमों की ब्रांडिंग की। उन्हें दुनिया के बाजार में पहुंचाया। सीएम ने सपा पर प्रहार करते हुए कहा कि वे माफिया पालते थे। गरीब, किसान की सुनवाई नहीं होती थी। हमने वोटबैंक नहीं देखा, बल्कि ह्यसबका साथ-सबका विकासह्ण के भाव संग कार्य कर रहे हैं।

बाबूपुर कचनारी में स्व. ठाकुर धर्मगज सिंह सोमवंशी की प्रतिमा का अनावरण, 'अपना घर' वृद्धाश्रम का उद्घाटन

हरदोई। ग्राम बाबूपुर कचनारी में आयोजित भव्य समारोह में उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने जननायक समाज के मार्गदर्शक स्वर्गीय ठाकुर धर्मगज सिंह सोमवंशी (पूर्व सांसद एवं विधायक) की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर देशराज सेवा संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा स्थापित 'अपना घर' वृद्धाश्रम का उद्घाटन भी किया गया।

पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह बोले– समाज सेवा, बुजुर्गों का सम्मान और सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण सरकार की प्राथमिकता

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

कार्यक्रम की शुरूआत वृद्धाश्रम परिसर में 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के तहत पौधरोपण से हुई। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए लोगों से अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनके संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। कार्यक्रम में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने भी पौधरोपण किया। समारोह के दौरान आयोजित जनसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ऑनलाइन संबोधन प्रसारित किया गया। उन्होंने स्वर्गीय ठाकुर धर्मगज सिंह सोमवंशी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रतिमा अनावरण और वृद्धाश्रम के उद्घाटन पर सभी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि धर्मगज सिंह का जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित रहा और वृद्धाश्रम जैसी सेवा परियोजना उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी।

अपने संबोधन में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि स्वर्गीय ठाकुर धर्मगज सिंह सोमवंशी का संपूर्ण राजनीतिक जीवन जनसेवा और सामाजिक सरोकारों के लिए समर्पित रहा। उनके विचार आज भी समाज के लिए प्रेरणास्रोत हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं। शिक्षा, जनकल्याण और समाज के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने बुजुर्गों के सम्मान, सनातन संस्कृति के संरक्षण तथा सामाजिक मूल्यों को मजबूत करने पर भी बल दिया और सफल आयोजन के लिए आयोजकों को बधाई दी।

कार्यक्रम को सांसद जय प्रकाश रावत, विधायक माधवेन्द्र प्रताप सिंह 'रानू' तथा विधायक श्याम प्रकाश ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत सिंह 'बब्बन', वरिष्ठ नेता डॉ. अशोक बाजपेयी, संबंधित अधिकारी, जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक उपस्थित रहे।

संक्षिप्त वार्ता

हरदोई जिला कारागार में विधिक जागरूकता शिविर

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई के तत्वावधान में सोमवार को जिला कारागार हरदोई में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान सिविल जज (सीनियर डिवीजन) एवं प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्मिता गोस्वामी ने कारागार का निरीक्षण किया तथा बंदियों को उनके विधिक अधिकारों और प्ली-बारगेनिंग के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।

उन्होंने बंदियों को बताया कि जिन कैदियों की आर्थिक स्थिति कमजोर है और जो निजी अधिवक्ता नियुक्त करने में असमर्थ हैं, वे कारागार अधीक्षक के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रार्थना-पत्र देकर निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। प्राधिकरण उनके मुकदमों की निःशुल्क पैरवी के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा।

वृहद वृक्षारोपण अभियान की तैयारियों के संबंध में जिलाधिकारी ने की समीक्षा बैठक

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई।आज विवेकानन्द सभागार मे जिलाधिकारी अनुनय झा की अध्यक्षता में 12 जुलाई को आयोजित होने वाले वृहद वृक्षारोपण अभियान की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक की गई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा की गई तैयारियों की विस्तार से समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने अभियान को सफल बनाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण पौधों का चयन, गड्ढों की समय से तैयारी, पौधों की उपलब्धता, सिंचाई, सुरक्षा एवं नियमित देखभाल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण स्थलों का पूर्व निरीक्षण कर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पूर्ण कर ली जाएं। लगाए जाने वाले पौधों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि उनकी अधिकतम जीवित रहने की संभावना सुनिश्चित हो सके।

पूर्वांचल में उभरता नाम हसीब खान क्या कांग्रेस को मिलेगी नई ताकत

वेब वार्ता, कमर खान

बलरामपुर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों जिस नाम की चर्चा लगातार बढ़ रही है, वह है हसीब खान। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने सक्रिय राजनीति करते हुए अपने एक अलग पहचान बनाई है, जिससे उनके कांग्रेस में शामिल होने के बाद उनका राजनीतिक सफर एक नए चरण में प्रवेश करता दिखाई दे रहा है। साल 2021 में राजनीति में कदम रखने वाले हसीब खान ने खुद को केवल चुनावी राजनीति तक सीमित रखने के बजाय जनसंपर्क और सामाजिक गतिविधियों के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास किया और सफल भी रहे। हसीब खान ने 2022 के विधानसभा चुनाव में जनवादी पार्टी को पूर्वांचल की चर्चित तीन सीटें दिलाई वो तब जब जनवादी पार्टी एक स्थानीय छोटी पार्टी थी।अगर हसीब खान एक छोटी सी पार्टी को 3 सीटें दिला सकते हैं तो वो कांग्रेस के लिए सीटों की गिनती काफी ज्यादा हो सकती है। उनके समर्थकों का कहना है कि उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में लोगों से लगातार संवाद बनाए रखा और स्थानीय मुद्दों को उठाने की कोशिश की। यही वजह है कि पूर्वांचल की राजनीति में उनका नाम समय-समय पर चर्चा का विषय बनता रहा है। हाल ही में हसीब खान ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की, जिसके बाद उनका दिल्ली दौरा भी सुर्खियों में रहा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। इन बैठकों में उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति, संगठन को मजबूत करने और भविष्य की रणनीति जैसे विषयों पर चर्चा होने की जानकारी सामने आई। राजनितिक जानकारों का कहना है की उनके संपर्क में कई छोटे राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और विभिन्न सामाजिक समुदायों के लोग हैं। जिनमे राजभर, निषाद, चौहान समाज सहित कई वर्गों के लोग कांग्रेस के साथ जुड़ सकते हैं।अगर इन सभी छोटे दल हसीब खान के कहने से कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं तो इससे हसीब खान का कद काफी बढ़ जायेगा, जिससे और आने वाले समय में राहुल गाँधी के काफी करीबी भी हो सकते हैं।राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि किसी भी नेता की वास्तविक राजनीतिक ताकत केवल लोकप्रियता से नहीं, बल्कि संगठन में उसकी भूमिका, जनाधार और चुनावी प्रदर्शन से तय होती है। ऐसे में कांग्रेस में हसीब खान की नई जिम्मेदारियां और आने वाले समय में उनकी सक्रियता यह तय करेगी कि वह पूर्वांचल की राजनीति में कितना प्रभाव छोड़ पाते हैं।

पचपेड़वा में मिट्टीलोक नर्सरी का बड़ा कदम दो साल में एक लाख पौधरोपण का संकल्प

वेब वार्ता, कमर खान

पचपेड़वा / बलरामपुर। पर्यावरण संरक्षण एवं हरित भविष्य के संकल्प के साथ मिट्टीलोक नर्सरी द्वारा दो वर्षीय एक लाख पौधरोपण अभियान की शुरूआत की गई। अभियान के प्रथम चरण में 200 पौधों का रोपण किया गया। इस अवसर पर नर्सरी के फाउंडर गौरव श्रीवास्तव एवं को फाउंडर मोहम्मद शफक ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य केवल पौधरोपण करना ही नहीं, बल्कि अधिक से अधिक लोगों को वृक्षारोपण के प्रति जागरूक करना भी है। उन्होंने कहा कि प्रकृति के संरक्षण के लिए सामूहिक भागीदारी बेहद आवश्यक है।

कार्यक्रम में एसएसबी के अधिकारी, चेयरमैन पचपेड़वा रवि वर्मा, चेयरमैन गैंसड़ी प्रिंस वर्मा, ब्लॉक प्रमुख पचपेड़वा मनोज कुमार तिवारी सहित अनेक गणमान्य एवं सम्मानित अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। सभी अतिथियों ने पौधरोपण कर अभियान की सराहना की और इसे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया।

संदिग्ध परिस्थितियों में महिला बाबू का शव उसके कमरे में मिला

कानपुर। श्रमायुक्त कार्यालय में प्रधान लिपिक के पद पर कार्यरत महिला बाबू की संदिग्ध परिस्थितियों में उसके कमरे में शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस घटना की जांच कर रही है। कल्याणपुर निवासी सुधा भारती श्रमायुक्त कार्यालय के बीओसी विभाग में बतौर प्रधान लिपिक के पद पर कार्यरत थी। विभागीय सूत्रों ने बताया कि सुधा और उसके पति से 10 वर्षों से अनबन चल रही थी। दोनों पति पत्नी एक ही मकान में ऊपर नीचे अलग अलग रह रहे थे। सुधा भारती के एक बेटी (16) व बेटा (11) साल का है। पति पीएसआईटी में लाइब्रेरियन के पद पर है। वही परिजनों के साथ आए लोगों ने विभाग के दिनेश बिष्ट और एएलसी सुमन सिंह पर काम को लेकर प्रताड़ित करना बताया है जिसके कारण काम का बोझ ज्यादा पड़ने और अधिकारियों की प्रताड़ना से परेशान हो कर सुधा ने ये कदम उठाया है। हालांकि परिजनों ने पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी है। पुलिस ने बताया कि मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चल सकेगी।

कार्यालय में काम के निर्देश के बाद बढ़ा विवाद, महिला लेखपाल ने एसडीएम पर लगाए गंभीर आरोप

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। शाहाबाद तहसील में कार्यालय में नियमित रूप से शासकीय कार्य करने के निर्देश से शुरू हुआ विवाद अब पुलिस और प्रशासन तक पहुंच गया है।

तहसील में तैनात महिला लेखपाल पूजा देवी ने एसडीएम सुशील कुमार मिश्रा पर छेड़छाड़, जातिसूचक टिप्पणी, अभद्र व्यवहार और निलंबन की धमकी देने का आरोप लगाते हुए कोतवाली शाहाबाद में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। वहीं, एसडीएम ने आरोपों को निराधार बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। दोनों पक्षों के बयान सामने आने के बाद मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है।

जानकारी के अनुसार, एसडीएम सुशील कुमार मिश्रा ने महिला लेखपाल पूजा देवी को नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित होकर शासकीय कार्य करने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में छह जुलाई की शाम उन्हें अपने कार्यालय कक्ष में बुलाया गया। महिला लेखपाल का आरोप है कि बातचीत के दौरान उनसे उनकी जाति पूछी गई, निजी कार्य करने का दबाव बनाया गया और विरोध करने पर उनके साथ छेड़छाड़ तथा अभद्र व्यवहार किया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें निलंबित कराने की धमकी दी गई।

घटना के बाद महिला लेखपाल ने कोतवाली शाहाबाद पहुंचकर एसडीएम के विरुद्ध तहरीर दी और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की। उनका कहना है कि बिलग्राम तहसील से शाहाबाद स्थानांतरण के बाद से ही उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था और यह घटना उसी क्रम की कड़ी है। घटना की जानकारी मिलने पर महिला लेखपाल के पिता एवं शाहाबाद तहसील में अधिवक्ता के रूप में कार्यरत राकेश कुमार वर्मा अपने साथी अधिवक्ताओं के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचे। आरोप है कि इस दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। महिला लेखपाल का आरोप है कि एसडीएम ने उनके पिता के साथ भी अभद्र व्यवहार किया और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्हें कार्यालय से बाहर निकलवा दिया। इस पूरे घटनाक्रम के वीडियो और दोनों पक्षों के बयान सामने आने के बाद मामला और अधिक चर्चा में आ गया। दूसरी ओर, एसडीएम सुशील कुमार मिश्रा का कहना है कि उन्होंने महिला लेखपाल को केवल शासकीय कार्य के संबंध में निर्देश दिए थे। उनके अनुसार, बाद में कुछ लोग कार्यालय में पहुंच गए और सरकारी कार्य में व्यवधान उत्पन्न करते हुए अभद्र व्यवहार करने लगे। उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को असत्य बताते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

फिलहाल पुलिस को महिला लेखपाल की तहरीर प्राप्त हो चुकी है और मामले की जांच की जा रही है।

घटना ने काफी सुर्खियाँ बटोरी थीं

गौरतलब है कि यह पहला अवसर नहीं है जब शाहाबाद तहसील किसी विवाद को लेकर सुर्खियों में आई हो। इससे पहले परियलगांव स्थित अन्नपूर्णा भवन की जांच के दौरान भी विवाद की स्थिति बनी थी, जिसमें एसडीएम सुशील कुमार मिश्रा घायल हो गए थे और उनके सिर में चोट आई थी। उस घटना ने भी काफी सुर्खियां बटोरी थीं। अब महिला लेखपाल द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद एक बार फिर तहसील का प्रशासनिक माहौल चर्चा के केंद्र में आ गया है।

श्रीलंका में कैदियों ने मचाया कत्लेआम, 25 को मार डाला

सुरक्षाकर्मियों के छीने हथियार, 100 को किया लहूलुहान

कोलंबो। श्रीलंका की सबसे हाई-सिक्योरिटी कही जाने वाली जेल में कैदियों ने कत्लेआम मचा दिया। पश्चिमी तटीय शहर नेगोम्बो स्थित इस जेल में भीषण दंगा तब और भयावह हो गया जब दंगाई कैदियों ने सुरक्षाकर्मियों से हथियार छीन लिए, जिससे स्थिति पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो गई। अधिकारियों द्वारा जारी प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, इस भयावह हिंसा में कम से कम पच्चीस लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि सौ से अधिक कैदी और जेलकर्मी घायल हुए हैं। रविवार को शुरू हुई यह भयावह हिंसा अगले दिन सोमवार तक भी जारी रही, इस दौरान दंगाई कैदियों ने जेल के शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया, जिससे जेल प्रशासन के लिए हालात बेहद गंभीर हो गए। इस गंभीर स्थिति पर काबू पाने और हिंसा को रोकने के लिए पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) और दंगा नियंत्रण इकाइयों को तुरंत जेल में तैनात किया गया।

इस घटना ने श्रीलंका की जेल सुरक्षा प्रणाली, उसकी क्षमता से अधिक कैदियों की संख्या और जेलों के भीतर कथित आपराधिक नेटवर्कों की उपस्थिति पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। सरकार ने संकेत दिया है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर जेल सुरक्षा व्यवस्था में व्यापक और मूलभूत सुधार किए जा सकते हैं, ताकि ऐसी त्रासदियों को भविष्य में रोका जा सके और जेलों में शांति व व्यवस्था बहाल की जा सके। यह घटना देश की आपराधिक न्याय प्रणाली और जेल प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बनकर उभरी है। इस बीच, श्रीलंका के न्याय मंत्री हर्षणा नानायक्कारा ने इस पूरे घटनाक्रम पर एक विस्तृत रिपोर्ट तलब की है, ताकि जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। रविवार को एक मजिस्ट्रेट की देखरेख में प्रारंभिक जांच भी कराई गई, जिसने घटना की गंभीरता को रेखांकित किया। सरकार अब जेल की सुरक्षा व्यवस्था, जेलों के भीतर कथित ड्रग नेटवर्क के पनपने और क्षमता से अधिक कैदियों की भीड़भाड़ जैसी गंभीर समस्याओं की समीक्षा कर रही है।प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि इस घातक झड़प की जड़ें जेल के भीतर सक्रिय दो प्रतिद्वंद्वी कैदी गुटों के बीच गहरे मतभेदों में थीं। अधिकारियों का मानना है कि एक गुट जेल के अंदर मादक पदार्थों की तस्करी का समर्थन करता था, जबकि दूसरा गुट इस अवैध गतिविधि का कड़ा विरोध कर रहा था। यह विवाद देखते ही देखते एक भीषण और हिंसक संघर्ष में बदल गया, जिसने जेल की शांति और व्यवस्था को पूरी तरह भंग कर दिया।

नशे की तस्करी को लेकर हुआ विवाद

लंबे और अथक अभियान के बाद ही स्थिति को आखिरकार नियंत्रित किया जा सका। हिंसा को आगे फैलने से रोकने और संभावित प्रतिशोध से बचने के लिए, अधिकारियों ने तीन प्रमुख कैदियों को तत्काल प्रभाव से पल्लानसेना प्रिजन कैंप में स्थानांतरित कर दिया। जेल प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह कदम भविष्य में होने वाली किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए उठाया गया था। जेल विभाग के मीडिया प्रवक्ता ए.सी. गजनायके ने पुष्टि की कि इस घटना की विस्तृत और गहन जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया गया है।

इंडो-पैसिफिक में नया अध्याय लिखने की तैयारी में भारत!

जकार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा का दूसरा दिन भारत-इंडोनेशिया संबंधों के इतिहास में एक नया मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। आज का दिन राजनीतिक, रणनीतिक और जनसंपर्क (पीपुल-टू-पीपुल कनेक्ट) तीनों ही लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, जो दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। आज दिन की शुरूआत राष्ट्रपति प्रबोवो सुबिआंतो और प्रधानमंत्री मोदी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की द्विपक्षीय वार्ता से होगी। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) क्षेत्र में बदलते समीकरणों के बीच दोनों देशों की यह मुलाकात बेहद अहम है। इस बैठक में मुख्य रूप से इन मुद्दों पर चर्चा होनी है जिसमें रक्षा और समुद्री सुरक्षा में सहयोग को बढ़ाना, व्यापार-निवेश और डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के साथ ही हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए साझा कदम उठाना है।

द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया की संसद ह्यकोम्प्लेक्स पालेर्मेन रिपब्लिक इंडोनेशियाह्ल पहुंचेंगे। वहां वे सांसदों को एक विशेष कार्यक्रम के तहत संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का यह संबोधन भारत-इंडोनेशिया की लोकतांत्रिक साझेदारी के साथ-साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों को एक नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। संसद का यह संबोधन दोनों देशों के बीच केवल सरकारी स्तर पर ही नहीं, बल्कि विधायी और लोकतांत्रिक स्तर पर भी संबंधों को मजबूत करेगा।

प्रवासी भारतीयों से संवाद

दिन के अंतिम पड़ाव में प्रधानमंत्री मोदी जकार्ता में भारतीय समुदाय के एक बड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे। अपने इस संबोधन में प्रधानमंत्री भारत की तेज विकास यात्रा और वैश्विक मंच पर देश की बढ़ती धाक का जिक्र करेंगे। साथ ही, वे भारत-इंडोनेशिया के सदियों पुराने सांस्कृतिक और जन-जन के रिश्तों को और प्रगाढ़ करने पर जोर देंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से न केवल दोनों देशों के कूटनीतिक संबंध मजबूत होंगे, बल्कि दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में भारत की एक्ट ईस्ट नीति को एक नई गति मिलेगी।

खेतों से लेकर फैक्ट्री तक काम करेंगे चीनी रोबोट

बीजिंग। चीन ने एक बार फिर अपनी तकनीकी क्षमताओं का लोहा मनवाया है। दुनिया में जहां इंसानी शिक्षा के मॉडल विकसित किए जा रहे हैं, वहीं चीन ने एक नई क्रांति की शुरूआत कर दी है। शंघाई में दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ट्रेनिंग सेंटर खुल चुका है, जो अब तक की सबसे अनोखी पहल है। यहां सिर्फ इंसान नहीं, बल्कि 100 से अधिक इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोटों को उन सभी कामों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो हम अपने रोजमर्रा के जीवन में करते हैं। चाहे वह खेत हों या फैक्ट्रियां, घर हों या अस्पताल। यह दर्शाता है कि भविष्य में रोबोट हमारी ज़िंदगी का एक अभिन्न और सक्रिय हिस्सा बनने वाले हैं, और चीन इस बदलाव में सबसे आगे रहना चाहता है। इस अनूठे प्रशिक्षण केंद्र में रोबोटों को शुरूआत में लगभग 45 बुनियादी काम सिखाए जाएंगे। इनमें सामान्य वस्तुओं को उठाना, पकड़ना, सही जगह पर रखना और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना शामिल है। ये ऐसे कार्य हैं जो औद्योगिक और घरेलू दोनों ही परिवेशों में अत्यंत आवश्यक होते हैं। धीरे-धीरे उन्हें अधिक जटिल कार्यों के लिए भी तैयार किया जाएगा, जैसे कपड़े मोड़ना, अलमारियां साफ करना, नाजुक गैजेट्स की सफाई करना और अन्य घरेलू व औद्योगिक कार्य। दिलचस्प बात यह है कि इंसानों के लिए आसान लगने वाला टी-शर्ट मोड़ना भी इन रोबोटों के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण कामों में से एक माना जाता है, जिस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि वे मानवीय निपुणता के करीब पहुंच सकें।

होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर लगेगा शुल्क, भारत को राहत!

नई दिल्ली। ईरान ने संकेत दिया है कि भविष्य में होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों से सेवा शुल्क लिया जा सकता है। हालांकि, तेहरान ने यह भी स्पष्ट किया है कि मित्र देशों के लिए विशेष रियायत पर विचार किया जाएगा। इस बयान के बाद दुनिया के कई देशों की नजर इस फैसले पर टिक गई है, क्योंकि होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति का प्रमुख समुद्री मार्ग माना जाता है। ऐसे में माना जा रहा है कि यदि ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों पर सेवा शुल्क लागू भी करता है, तो भारत को मित्र देश का दर्जा मिलने के कारण विशेष छूट या रियायत मिल सकती है। हालांकि, इस संबंध में अंतिम स्थिति ईरान की आधिकारिक नीति और आगामी दिशा-निर्देश जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।

चीन में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान ईरान के एक वरिष्ठ राजनयिक ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य का एक हिस्सा ईरान के क्षेत्रीय जल में आता है। ऐसे में वहां से गुजरने वाले जहाजों से सेवा शुल्क लेना स्वाभाविक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसे पारंपरिक टोल टैक्स के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि समुद्री सेवाओं से जुड़े शुल्क के तौर पर समझा जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन देशों ने कठिन समय में ईरान का साथ दिया है, उनके लिए विशेष व्यवस्था की जा सकती है। हालांकि, ईरान ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह शुल्क कब से लागू होगा, इसकी दर क्या होगी और किन देशों या जहाजों पर यह लागू किया जाएगा। साथ ही यह भी नहीं बताया गया है कि किन मित्र देशों को इससे छूट मिलेगी। भारत के संदर्भ में यह घोषणा राहत देने वाली मानी जा रही है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से रणनीतिक और आर्थिक संबंध रहे हैं। अतीत में भी तनावपूर्ण परिस्थितियों के दौरान ईरान ने भारतीय जहाजों के प्रति अपेक्षाकृत नरम रुख अपनाया था। जब क्षेत्रीय सुरक्षा कारणों से समुद्री आवाजाही प्रभावित हुई थी, तब भी भारतीय जहाजों को विशेष अनुमति दिए जाने की घटनाएं सामने आई थीं।

तेहरान से कोम पहुंचा खामेनेई का पार्थिव शरीर

तेहरान। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई का पार्थिव शरीर सोमवार शाम राजधानी तेहरान से धार्मिक नगरी कोम पहुंच गया। ईरान के सरकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पार्थिव शरीर को हेलिकॉप्टर के जरिए कोम लाया गया, जहां अंतिम यात्रा के साथ पारंपरिक धार्मिक रस्में पूरी की जा रही हैं। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके गृह नगर मशहद ले जाया जाएगा, जहां गुरुवार को इमाम रजा दरगाह परिसर में उन्हें सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा।

यहां बताते चलें कि कोम ईरान के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक शहरों में से एक माना जाता है और शिया मुसलमानों का प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र है। अयातुल्ला खामेनेई ने अपनी प्रारंभिक और उच्च धार्मिक शिक्षा इसी शहर में प्राप्त की थी। यहीं से उन्होंने इस्लामी अध्ययन और धार्मिक नेतृत्व की दिशा में अपनी पहचान बनाई, जिसके बाद वे देश के सबसे प्रभावशाली धार्मिक नेताओं में शामिल हुए।

इससे पहले तेहरान में लगातार तीसरे दिन भी खामेनेई की अंतिम यात्रा में जनसैलाब उमड़ा। राजधानी की सड़कों पर लाखों लोगों ने अपने दिवंगत नेता को अंतिम विदाई दी। बड़ी संख्या में लोग हाथों में धार्मिक झंडे और बैनर लेकर अंतिम यात्रा में शामिल हुए। श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे लोगों ने खामेनेई तथा उनके परिवार के दिवंगत सदस्यों के ताबूतों पर फूल बरसाए और उनके सम्मान में प्रार्थनाएं कीं।

भारी भीड़ के कारण अंतिम यात्रा कई स्थानों पर धीमी गति से आगे बढ़ी। आजादी स्ट्रीट पर भी ताबूत ले जा रहा वाहन कुछ समय के लिए रुक गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने अंतिम दर्शन किए। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए थे और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी पूरे मार्ग पर तैनात रहे।

सरकारी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कोम में धार्मिक परंपराओं के अनुसार अंतिम रस्में संपन्न होने के बाद पार्थिव शरीर को मशहद ले जाया जाएगा। गुरुवार को इमाम रजा दरगाह परिसर में पूरे राजकीय और धार्मिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस दौरान देश के वरिष्ठ धार्मिक नेताओं, सरकारी प्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में आम नागरिकों के शामिल होने की संभावना है।

मुनीर को कहां से मिली भारत को धमकाने की ताकत?

नई दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत से मुंह की खा चुके पाकिस्तान की सेना प्रमुख आसिम मुनीर को इतना आत्मविश्वास कहां से मिल रहा है? कि वे भारत के खिलाफ बोल सकें। कहीं इसके पीछे यूक्रेन का वह अप्रत्याशित सहयोग तो नहीं है, जिसे भारत ने कुछ महीने पहले उजागर किया था। भारतीय सीमा पर अपने लगभग 600 ड्रोन गंवाने के बाद, ऐसी खबरें हैं कि यूक्रेन अब पाकिस्तानी सेना को आधुनिक ड्रोन युद्ध में प्रशिक्षित कर रहा है। ऐसे में यह जानना महत्वपूर्ण है कि यूक्रेन आखिर पाकिस्तानी सेना को कौन सी नई रणनीतियाँ सिखा रहा है, जिससे उनका आत्मविश्वास इतना बढ़ गया है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर, सिंधु नदी समझौता रद्द होने की संभावना से बौखलाए हुए प्रतीत होते हैं। हाल के बयानों में वह भारत के खिलाफ हर तरीका इस्तेमाल करने की धमकी दे रहे हैं, जिससे उनकी आक्रामक मानसिकता स्पष्ट होती है। हालांकि, यह सवाल उठता है कि पिछले साल, पाकिस्तानी सेना ने भारत के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी और आधुनिक साजिश रचने का प्रयास किया था, जिसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया था। पाकिस्तान ने भारतीय सीमाओं के भीतर महत्वपूर्ण सैन्य और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने के लिए एक साथ लगभग 600 ड्रोन्स का इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी। हालांकि, पाकिस्तानी सेना का यह संपूर्ण ड्रोन ऑपरेशन एक बहुत बड़ी विफलता साबित हुआ। पाकिस्तानी सेना के अधिकांश ड्रोन या तो भारतीय सेना ने सीमा पर ही मार गिराए, या फिर वे तकनीकी कमियों और खराब रखरखाव की वजह से खुद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गए। हालांकि, कुछ ड्रोन्स का मलबा रिहायशी इलाकों में गिरने से आम नागरिकों को थोड़ा नुकसान अवश्य हुआ, लेकिन कुल मिलाकर भारत ने पाकिस्तान के इस मेगा ड्रोन प्लान को पूरी तरह से विफल कर दिया। इस करारी हार ने पाकिस्तानी सेना को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि उनकी मौजूदा ड्रोन तकनीक और रणनीति भारत के सामने बेहद कमजोर और अप्रभावी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिली शर्मनाक हार और भारत के खिलाफ बार-बार विफल हुई साजिशों के बाद अपनी कमजोरियों को छिपाने और आधुनिक ड्रोन वॉरफेयर तकनीक सीखने के लिए पाकिस्तान ने अपने पुराने सहयोगी देश यूक्रेन का रुख किया। यूक्रेन पिछले कई सालों से रूस के खिलाफ एक बेहद भीषण और हाई-टेक युद्ध लड़ रहा है, जिसमें ड्रोन तकनीक का सबसे ज्यादा, सबसे प्रभावी और विनाशकारी इस्तेमाल हुआ है। लगातार चल रही इस जंग ने यूक्रेन को ड्रोन ऑपरेशन्स, कामिकेज ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में दुनिया का सबसे अनुभवी और बैटल-हार्डन्ड देश बना दिया है।

तेजस बनेगा और घातक, ब्रह्मोस के बाद ब्रह्मास्त्र से होगा लैस

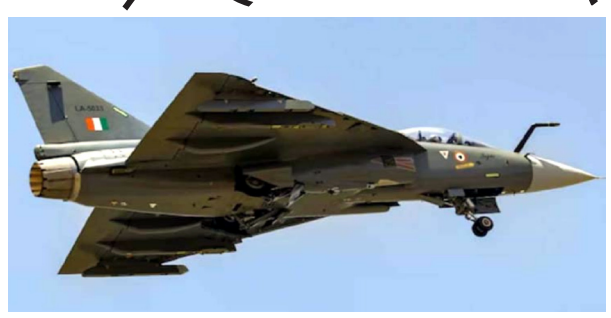

नई दिल्ली। भारत अपनी सैन्य ताकत और हवाई संप्रभुता को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए लगातार स्वदेशी रक्षा तकनीकों का विकास कर रहा है। मिसाइल, ड्रोन, युद्धपोत और पनडुब्बियों के बाद अब वायुसेना के बेड़े से एक बेहद बड़ी खुशखबरी सामने आई है। देसी राफेल के नाम से मशहूर और फ्रांसीसी राफेल जेट के मुकाबले बेहद किफायती स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस को एक ऐसे नए वेपन सिस्टम से लैस करने की तैयारी चल रही है, जो दुश्मन की मांद में घुसकर तबाही मचाने में सक्षम है। तेजस जेट में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का इंटीग्रेशन पहले से ही तय है, लेकिन अब नए आत्मघाती हथियारों के जुड़ने से यह फाइटर जेट विरोधियों के लिए काल बन जाएगा।

भारतीय वायुसेना की योजना अपने स्वदेशी तेजस एमके1ए और आगामी तेजस एमके2 लड़ाकू विमानों को एयर लॉन्च्ड लॉयटरिंग म्यूनिशंस (कामिकाजे ड्रोन) और भविष्य के मानवरहित सहयोगी लड़ाकू विमानों (कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी सीसीए) से लैस करने की है। इस रणनीति का मुख्य उद्देश्य पायलटों को सुरक्षित रखते हुए दुश्मन के सबसे सुरक्षित और संवेदनशील इलाकों में गहरे तक सटीक हमले करना है। इसके लिए भारतीय वायुसेना वैश्विक स्तर पर अपनाई जा रही मैन्ड-अनमैन्ड टीमिंग (एमयूएम-टी) अवधारणा को अपना रही है। इस तकनीक के तहत मानव संचालित लड़ाकू विमान स्वायत्त ड्रोन और रोबोटिक विंगमैन के साथ मिलकर हवा में अभियान चलाएंगे, जिससे विमान दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली की रेंज से बाहर रहकर भी प्रभावी हमला कर सकेंगे। योजना के पहले चरण में तेजस विमानों को एयर लॉन्च्ड लॉयटरिंग म्यूनिशंस से लैस किया जाएगा, जिनकी मारक क्षमता 150 से 300 किलोमीटर तक होगी। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड का कैट्स अल्फा (सीएटीएस एल्फा) प्रोग्राम इस आवश्यकता को पूरा करेगा। लड़ाकू विमान से अत्यधिक ऊंचाई और तेज गति पर छोड़े जाने वाले ये ड्रोन दुश्मन के रडार स्टेशन, कमांड सेंटर और मिसाइल प्रणालियों को पलक झपकते ही तबाह कर देंगे। इससे मानवीय पायलटों को सबसे खतरनाक युद्ध क्षेत्रों में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरे चरण में भारतीय वायुसेना अपने लड़ाकू विमानों को उड़ते हुए कमांड सेंटर (मदर शिप) में तब्दील करेगी। इस चरण के तहत तेजस विमान हवा में ही लॉयल विंगमैन और फ्लीट आकार के सीसीए ड्रोन को नियंत्रित करेंगे। इसके लिए एचएएल का कैट्स वॉरियर कार्यक्रम तेजी से काम कर रहा है। इन रोबोटिक विंगमैन की ऑपरेशनल क्षमता 400 से 600 किलोमीटर तक होगी। ये ड्रोन सिर्फ आत्मघाती हथियार नहीं होंगे, बल्कि आक्रामक और रक्षात्मक दोनों अभियानों में मानव पायलट के साथ एक बुद्धिमान सहयोगी के रूप में काम करेंगे। इस तकनीक के शामिल होने के बाद भारतीय तेजस फाइटर जेट वैश्विक स्तर पर आधुनिक हवाई युद्ध के तौर-तरीकों को पूरी तरह बदल कर रख देगा।

ईरान युद्ध के बाद ट्रंप-नेतन्याहू मुलाकात की बढ़ी संभावना

वाशिंगटन। इजरायल और अमेरिका के संयुक्त ऑपरेशन ने ईरान में जो तबाही मचाई है, उसके नतीजतन पूरी दुनिया की राजनीति में उथल-पुथल मची हुई है। अब इस समस्या का हल निकालने में खुद अमेरिका के पसीने छूट रहे हैं। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इजरायल के उकसावे में ही ट्रंप ने यह कदम उठाया था, और अब जब अमेरिका शांति चाहता है, तो इजरायल ऐसा नहीं चाहता। इन सबके बीच एक दिलचस्प खबर यह आ रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जल्द ही इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से व्हाइट हाउस में मुलाकात हो सकती है।

नागपुर के घर में कोबरा के 40 बच्चे मिलने से मचा हड़कंप

स्नेक रेस्क्यू टीम ने पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा

नागपुर। महाराष्ट्र के नागपुर जिले के रामटेक तालुका स्थित नेरला गांव में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक घर के भीतर कोबरा सांप के 40 बच्चे एक साथ रेंगते नजर आए। यह घटना गांव निवासी राजू धोमने के घर की है।

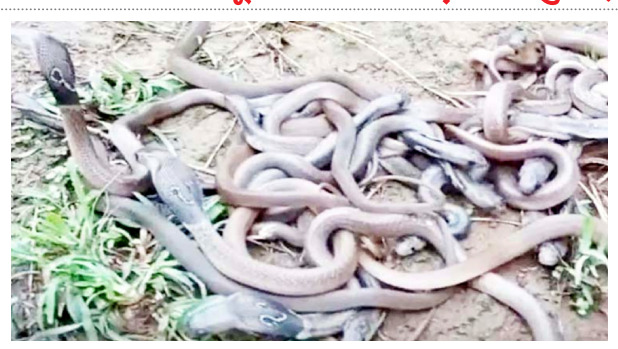

बड़ी संख्या में जहरीले सांपों के बच्चे मिलने से परिवार और आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि, स्नेक रेस्क्यू टीम और वन विभाग की त्वरित कार्रवाई से सभी कोबरा के बच्चों को सुरक्षित पकड़कर उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया।

जानकारी के अनुसार, मानसून की शुरूआत के बाद लगातार बारिश से सांपों के बिलों में पानी भर गया है। इसी कारण कई सांप और अन्य सरीसृप सुरक्षित स्थान की तलाश में रिहायशी इलाकों की ओर निकल रहे हैं। इसी दौरान राजू धोमने के घर के एक हिस्से में कोबरा के कई बच्चे दिखाई दिए। परिवार ने बिना जोखिम उठाए तुरंत स्नेक रेस्क्यूअर्स को सूचना दी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सूचना मिलते ही चाचर स्थित वाइल्ड चैलेंजर ऑर्गनाइजेशन के स्नेक रेस्क्यूअर एवं पशु कल्याण कार्यकर्ता रतन कुंभारे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। एक ही स्थान पर बड़ी संख्या में कोबरा के बच्चे होने के कारण बचाव अभियान बेहद सावधानी से चलाया गया। टीम ने सभी 40 बच्चों को सुरक्षित तरीके से पकड़ लिया।

घटना की सूचना मिलने पर रामटेक वन विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। सहायक वन संरक्षक (एसीएफ) गोविंद कुमार लुचे और रेंज ऑफिसर राहुल शिंदे ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने मीडिया को बताया कि वन्यजीव संरक्षण नियमों का पालन करते हुए सभी कोबरा के बच्चों को सुरक्षित रूप से जंगल में उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया है। सहायक वन संरक्षक गोविंद कुमार लुचे ने स्नेक रेस्क्यू टीम के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि मानसून के दौरान सांपों का बाहर निकलना सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि सांप दिखाई देने पर उसे मारने या स्वयं पकड़ने का प्रयास न करें, बल्कि तुरंत वन विभाग या प्रशिक्षित स्नेक रेस्क्यूअर्स को सूचना दें।

रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमता का उपयोग मानव कल्याण के लिए हो :राज्यपाल डेका

रायपुर. राज्यपाल श्री रमेन डेका ने भारत सेवाश्रम संघ द्वारा संचालित प्रणवानंद अकादमी में रोबोटिक्स लैबोरेट्री का लोकार्पण किया। इस लैबोरेट्री की स्थापना के लिए राज्यपाल द्वारा अपने स्वेछानुदान मद से राशि प्रदान की गई है। इस अवसर पर राज्यपाल ने अपने संबोधन ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमता, रोबोटिक्स जैसे तकनीक हमारे जीवन को आसान बनाते है। लेकिन आधुनिक तकनीक तभी सार्थक है, जब उसका उपयोग मानव जीवन के कल्याण और समाज के विकास के लिए किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी शिक्षण संस्थान की वास्तविक पहचान केवल उत्कृष्ट परीक्षा परिणामों से नहीं होती, बल्कि ऐसे विद्यार्थियों से होती है जो ज्ञान के साथ मानवीय मूल्यों, संवेदनशीलता और सामाजिक

उत्तरदायित्व का परिचय दें। प्रणवानंद अकादमी शिक्षा के साथ-साथ संस्कार, अनुशासन और चरित्र निर्माण को भी समान महत्व देता है यह प्रसन्नता का विषय है। राज्यपाल ने कहा कि आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता रोबोटिक्स और अन्य आधुनिक तकनीकें विश्व को नई दिशा दे रही हैं। ऐसे समय में विद्यार्थियों को तकनीकी ज्ञान के साथ नैतिक मूल्यों को भी आत्मसात करना चाहिए। कोई भी नया आविष्कार या नवाचार मानवता के हित में होना चाहिए। मानव पर खुद का नियंत्रण होना चाहिए न कि कोई तकनीक उसे नियंत्रित करे। राज्यपाल ने विद्यार्थियों को जीवन मूल्यों का संदेश देते हुए कहा कि जीवन में संतोष का विशेष महत्व है। हमें जो प्राप्त है, उसमें प्रसन्न रहना सीखना चाहिए तथा कठिन परिश्रम, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में उतार-चढ़ाव एवं चुनौतियाँ आती हैं, लेकिन गिरने के बाद फिर से उठना और आगे बढ़ना ही सफलता का मार्ग है। उन्होंने कहा कि समाज ने हमें क्या दिया, यह सोचने के बजाय हमें यह विचार करना चाहिए कि हम समाज को क्या दे सकते हैं। समाज के प्रति सेवा, सहयोग, संवेदनशीलता और पड़ोसियों के प्रति आत्मीयता की भावना हमारे जीवन में आनंद लाता है। कार्यक्रम में अकादमी के अध्यक्ष स्वामी श्री शिवरूपानंद ने स्वागत उद्बोधन दिया तथा प्राचार्य श्रीमती नीति यदुवंशी ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर संस्थान के पदाधिकारी, शिक्षकगण एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

ताजा खबर
संक्षिप्त

राज्यपाल डेका से मुख्यमंत्री साय ने सौजन्य भेंट

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका से आज लोकभवन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सौजन्य भेंट की। इस दौरान कैबिनेट के आईआईएम में दो दिवसीय चिंतन शिविर, विस के मानसून सत्र और प्रस्तावित यूसीसी कानून जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।

छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी में हज-2027 के ऑनलाइन आवेदन हेतु नि:शुल्क ई-सुविधा केंद्र शुरू

रायपुर. हज 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। हज यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी ने मुखर्जी बड़ा, बैरन बाजार स्थित अपने कार्यालय में नि:शुल्क ई-हज सुविधा केंद्र प्रारंभ किया है। छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के चेयरमैन मिर्ज़ा एजाज़ बेग ने आज बताया कि इस केंद्र के माध्यम से हज 2027 के इच्छुक आवेदकों के ऑनलाइन आवेदन नि:शुल्क भरे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के चेयरमैन श्री बेग ने बताया कि अनेक आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन भरने में कठिनाई होती है। ऐसे में समय सीमा के भीतर आवेदन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से यह विशेष सुविधा उपलब्ध कराई गई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा हज 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास 31 दिसंबर 2027 तक वैध पासपोर्ट होना अनिवार्य है। श्री बेग ने हज यात्रा के इच्छुक सभी आवेदकों से निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व अपना ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी कार्यालय में इसके लिए एक विशेष काउंटर स्थापित किया गया है, जहां आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन भरवा सकते हैं। अधिक जानकारी अथवा ऑनलाइन आवेदन संबंधी सहायता के लिए कार्यालय, छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी, मुखर्जी बड़ा, बैरन बाजार, रायपुर अथवा दूरभाष क्रमांक 0771-4266646 पर संपर्क किया जा सकता है।

कोसा बीज केंद्र मोदकपाल से 5,700 तसर स्वस्थ डिम्ब समूहों का वितरण

रायपुर। राज्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत बीजापुर जिले में रेशम विभाग द्वारा संचालित कोसा बीज केंद्र, मोदकपाल में तसर पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हितग्राहियों को 5,700 तसर स्वस्थ डिम्ब समूहों का वितरण किया गया। इन डिम्ब समूहों की कुल लागत 91,200 रुपए रही। इसमें राज्य शासन ने 79,800 रुपए की सब्सिडी प्रदान की, जबकि हितग्राहियों से केवल 11,400 रुपए का अंशदान लिया गया। इससे कम लागत में गुणवत्तायुक्त तसर बीज उपलब्ध कराकर तसर पालन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

स्वस्थ छत्तीसगढ़ करेगा विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण : मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय

103 करोड़ रुपये से अधिक के स्वास्थ्य अधोसंरचना कार्यों का भूमिपूजन

200 सीटर छात्रावास, कैंसर भवन विस्तार और आवासीय परिसर का होगा निर्माण

रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अटल बिहारी वाजपेयी सभागृह, चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में 103 करोड़ रुपये से अधिक लागत के स्वास्थ्य अधोसंरचना विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वस्थ छत्तीसगढ़ ही विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करेगा। प्रदेश में लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। यह परियोजनाएं प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाई प्रदान करेंगी तथा मरीजों, विद्यार्थियों और चिकित्सकों सभी को इसका लाभ मिलेगा। इस अवसर पर छात्र-छात्राओं के लिए आधुनिक छात्रावास, कैंसर भवन के विस्तार तथा चिकित्सकों एवं कर्मचारियों के आवासीय परिसर सहित विभिन्न निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी गई। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पिछली बार मेडिकल कॉलेज आने पर विद्यार्थियों ने छात्रावास निर्माण की मांग रखी थी, जिसे सरकार ने गंभीरता से लेते हुए आज उसके निर्माण की शुरुआत कर दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले ढाई वर्षों में जनता से किए गए अधिकांश वादों को पूरा किया है और %मोदी की गारंटी% को धरातल पर उतारा है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और विकसित भारत के संकल्प की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए स्वस्थ छत्तीसगढ़ आवश्यक है। स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल के नेतृत्व में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग लगातार उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों एवं पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि केंद्र सरकार का छत्तीसगढ़ को निरंतर सहयोग मिल रहा है। उन्होंने

बताया कि डीएम कार्डियक कोर्स की स्वीकृति से लेकर अन्य स्वास्थ्य परियोजनाओं तक केंद्र सरकार ने हर मांग पर सकारात्मक सहयोग दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में छत्तीसगढ़ को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद) की भी सौगात मिलेगी, जिससे राज्य की समृद्ध औषधीय वनस्पतियों एवं आयुर्वेद को नई पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर अब नक्सलवाद से मुक्त होकर तेजी से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने दूरस्थ क्षेत्रों में घर-घर पहुंचकर लाखों लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार किया है। उन्होंने मेडिकल विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे अपनी पढ़ाई पूरी कर सरगुजा से लेकर बस्तर तक प्रदेश के हर क्षेत्र में सेवाएं देने का संकल्प लें और केवल शहरों तक सीमित रहने की मानसिकता न रखें। उन्होंने कहा कि सरकार चिकित्सा शिक्षा के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है तथा विद्यार्थियों को बेहतर अधोसंरचना, छात्रावास एवं आधुनिक शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा। उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि लगभग 104 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले छात्रावास, कैंसर संस्थान विस्तार एवं अन्य अधोसंरचना परियोजनाएं चिकित्सा क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि साबित होंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग एवं निर्माण एजेंसियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा से पहले एवं उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए जाएं।स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहा है। राज्य में पांच नए मेडिकल कॉलेजों की स्वीकृति, नर्सिंग कॉलेजों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि, फिजियोथेरेपी कॉलेजों का विस्तार तथा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए बड़े स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 10 एकड़ क्षेत्र में 100 बिस्तरों वाले योग एवं नेचुरोपैथी अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर का निर्माण भी प्रगति पर है। स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि राज्य सरकार ने पूर्व में लंबित कोरबा, कांकेर एवं महासमुंद मेडिकल कॉलेजों के निर्माण कार्य प्रारंभ कराए हैं। बिलासपुर स्थित सिम्स का भी व्यापक उन्नयन किया जा रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि डीएम कार्डियक कोर्स प्रारंभ हो चुका है तथा जगदलपुर में जल्द ही छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा हार्ट सेंटर स्थापित किया जाएगा।

कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रथम परियोजना के तहत 200 सीटर आधुनिक छात्र-छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। इसमें विद्यार्थियों के लिए आधुनिक आवासीय सुविधाओं के साथ चिकित्सकों एवं कर्मचारियों के लिए भी आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। दूसरी परियोजना के तहत कैंसर भवन का द्वितीय से छठे तल तक विस्तार किया जाएगा। लगभग 11 हजार वर्गमीटर क्षेत्र में बनने वाले इस भवन में आधुनिक लैब, 64-64 बिस्तरों वाले वार्ड, सिंगल रूम, आईसीयू तथा अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर विकसित किए जाएंगे, जिससे कैंसर रोगियों को उच्च स्तरीय उपचार सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

तीसरी परियोजना के अंतर्गत छात्राओं के लिए आधुनिक छात्रावास का विस्तार किया जाएगा, जिसमें अतिरिक्त कमरे, डॉरमेट्री, लाइब्रेरी, रिक्रिएशन हॉल तथा सभी आवश्यक आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी, ताकि छात्राओं को सुरक्षित एवं बेहतर आवासीय वातावरण उपलब्ध हो सके। इस अवसर पर विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, सीजीएमएससी के चेयरमैन श्री दीपक म्हस्के, स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री अमित कटारिया, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा श्री रितेश अग्रवाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के डीन डॉ. विवेक चौधरी, अधीक्षक डॉ. संतोष सोनकर सहित जनप्रतिनिधि, चिकित्सक, मेडिकल विद्यार्थी एवं बड़ी संख्या में नागरिकगण उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें किया नमन

रायपुर. मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में प्रख्यात शिक्षाविद् और राष्ट्रवादी चिंतक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए उनके छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी मां भारती के सच्चे सपूत थे, जिन्होंने राष्ट्र की अखंडता के लिए सर्वोच्च बलिदान देते हुए संपूर्ण जीवन देश सेवा के लिए समर्पित किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी के दिखाए पथ पर अग्रसर होते हुए हम विकसित और सशक्त भारत का निर्माण करेंगे। इस अवसर पर विधायक श्री पुरंदर मिश्रा सहित अन्य गणमान्यजन उपस्थित थे।

डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर राज्यपाल ने दी श्रद्धांजलि

रायपुर. प्रखर राष्ट्रवादी नेता एवं महान शिक्षाविद् डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर आज लोक भवन में राज्यपाल रमेन डेका ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी।

राज्यपाल ने कहा कि डॉ. मुखर्जी का राष्ट्र की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पण सभी देशवासियों के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने युवाओं से उनके आदर्शों को अपनाकर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। लोक भवन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

जिले में खरीफ सीजन के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध

रायपुर. खरीफ सीजन को देखते हुए जिले में किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जिले की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों एवं निजी उर्वरक विक्रेताओं के माध्यम से किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रशासन द्वारा उर्वरकों के भंडारण, वितरण एवं बिक्री की सतत निगरानी की जा रही है ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और कालाबाजारी जैसी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। कृषि विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में उर्वरक भण्डारण हेतु खरीफ वर्ष 2026 के लिए निर्धारित लक्ष्य का 59 प्रतिशत उर्वरक भण्डारण किया जा चुका है तथा लगभग 44 प्रतिशत उर्वरकों का वितरण किसानों को किया गया है। साथ ही जिले में 1 अप्रैल 2026 से अब तक यूरिया भण्डारण के निर्धारित लक्ष्य का 72 प्रतिशत भण्डारण किया जा चुका है। किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार सहकारी समितियों एवं अधिकृत निजी उर्वरक विक्रेताओं से यूरिया सहित अन्य उर्वरक प्राप्त कर सकते हैं। कृषि विभाग द्वारा किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान पर हरी खाद के ढैचा तथा मूंग के बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

बारिश के बीच अतिथि शिक्षकों ने किया शिक्षा मंत्री निवास का घेराव

दुर्ग। अनिश्चितकालीन हड़ताल के क्रम में अतिथि शिक्षकों ने रविवार को दुर्ग स्थित शिक्षा मंत्री निवास का घेराव किया। बारिश के बीच उन्होंने बड़े ही जोश के साथ रैली के शक्ल में सेवा सदन पहुंचे। हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा को देखते हुए बैरिकेट्स लगाए गए थे। इस वजह से ये शिक्षक नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपकर वापस धरना स्थल पर आ गये।बता दें कि राज्य अतिथि शिक्षक (विद्यामितान) कल्याण संघ छत्तीसगढ़ के आह्वान पर प्रदेशभर के राज्य अतिथि शिक्षकों ने बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है । शिक्षामंत्री के विधानसभा क्षेत्र दुर्ग में ही राज्य अतिथि शिक्षकों ने धरना-प्रदर्शन कर सरकार से वर्षों से लंबित मांगों पर तत्काल निर्णय लेने की मांग की। संघ का कहना है कि 10 वर्षों से प्रदेश की शासकीय

विद्यालयों में नियमित व्याख्याताओं के समान शैक्षणिक दायित्व निभाने के बावजूद राज्य अतिथि शिक्षकों को आज भी सम्मानजनक वेतन, सेवा सुरक्षा और वैधानिक सुविधाएं नहीं मिल सकी हैं। संघ के अनुसार प्रदेश के हजारों राज्य अतिथि शिक्षक लंबे समय से विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें मात्र 20 हजार रुपए मासिक मानदेय दिया जाता है, वह भी केवल 10 माह के लिए। वहीं ज़ समान कार्य करने वाले अन्य शिक्षक वर्गों को कई गुना अधिक वेतन, नियमित सेवा का दर्जा तथा सभी वैधानिक सुविधाएं प्राप्त हैं। इसे संघ ने समान कार्य, समान वेतन के सिद्धांत के विपरीत बताया है। संघ ने आरोप लगाया कि 10 वर्षों की सेवा के दौरान अतिथि शिक्षकों को ग्रीष्मकालीन अवकाश का वेतन नहीं दिया जाता, नियमित अवकाश का लाभ नहीं मिलता और मातृत्व अवकाश से संबंधित आदेशों का भी समुचित पालन नहीं हुआ। हर वर्ष नए शैक्षणिक सत्र के साथ सेवा जारी रहने की अनिश्चितता बनी रहती है, जिससे हजारों परिवार आर्थिक और मानसिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि विधानसभा, विभागीय बैठकों और विभिन्न मंचों पर राज्य अतिथि शिक्षकों की समस्याओं को कई बार उठाया गया। मोदी की गारंटी में भी राज्य अतिथि शिक्षक (विद्यामितान) के संविलियन/समायोजन का स्पष्ट वादा किया गया था।

छत्तीसगढ़ में निकायों को निर्देश, सीपीसीबी पोर्टल पर कराना होगा पंजीयन

सभी बल्क वेस्ट जनरेटर्स का होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

रायपुर. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों को बल्क वेस्ट जनरेटर्स (Bulk Waste Generators) का पंजीयन सुनिश्चित कराने के निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए विभाग ने सभी निकायों के आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को परिपत्र भेजा है।

विभाग ने बताया कि, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (ष्टक्कष्टक्क) ने बल्क वेस्ट जनरेटर्स के पंजीयन के लिए केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है, जो 1 जून 2026 से प्रभावी हो चुका है। अब चिन्हित सभी बल्क वेस्ट जनरेटर्स का इसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा।यह व्यवस्था ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के तहत लागू की गई है। इसके अनुसार बड़े स्तर पर कचरा उत्पन्न करने वाले संस्थानों, परिसरों और अन्य चिन्हित इकाइयों का पंजीयन केंद्रीकृत पोर्टल पर किया जाना आवश्यक है।नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी

नगरीय निकायों को निर्देश दिए हैं कि अपने-अपने क्षेत्र में चिन्हित सभी बल्क वेस्ट जनरेटर्स की पहचान कर उनका पंजीयन CPCB के ऑनलाइन पोर्टल पर जल्द से जल्द सुनिश्चित कराया जाए।

इससे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को बेहतर बनाने और नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। 19 दिन पहले पर्यावरण संरक्षण मंडल ने भी जारी किया था सख्त आदेश बल्क वेस्ट जनरेटर्स के पंजीयन को लेकर नगरीय प्रशासन विभाग के निर्देश ऐसे समय आए हैं, जब 19 दिन पहले छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने बैटरी वेस्ट के अवैध कारोबार पर सख्ती के आदेश जारी किए थे।

मंडल ने स्पष्ट किया था कि बिना पंजीयन और जरूरी दस्तावेजों के पुरानी बैटरियों की खरीद-बिक्री, भंडारण और परिवहन करना गैरकानूनी है। अधिकारियों के मुताबिक प्रदेश में कई स्थानों पर कबाड़ और पुरानी बैटरियों का कारोबार नियमों के विपरीत संचालित होने की शिकायतें मिली हैं, जिससे पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा बढ़ रहा है। बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2022 के तहत केवल पंजीकृत संस्थाओं को ही पुरानी बैटरियों का संग्रहण, भंडारण, परिवहन और रीसाइक्लिंग करने की अनुमति है। कारोबारियों के लिए खरीद-बिक्री और परिवहन से जुड़े सभी दस्तावेज रखना भी अनिवार्य किया गया है।

पर्यावरण संरक्षण मंडल ने यह भी साफ किया था कि खुले स्थान पर पुरानी बैटरियां जमा करना, बिना अनुमति उनका भंडारण करना या अवैध तरीके से खरीद-बिक्री करना कानून का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

मंडल ने पूरे प्रदेश में विशेष जांच अभियान चलाने की भी घोषणा की थी। इसके तहत स्क्रैप डीलरों, कबाड़ कारोबारियों, ट्रांसपोर्टरों और बैटरी व्यापार से जुड़े लोगों की जांच होगी। गंभीर अनियमितता मिलने पर केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

साथ ही आम लोगों से भी अपील की गई थी कि कहीं भी बैटरी वेस्ट का अवैध कारोबार, भंडारण या परिवहन दिखाई दे तो इसकी सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें।

आरक्षक प्रमोशन पर हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश, अगली सुनवाई तक नियुक्ति पर रोक

बिलासपुर। हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने राज्य में पुलिस आरक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया है। जस्टिस बीडी गुरु की कोर्ट ने कहा है कि विभाग पदोन्नति की प्रक्रिया को आगे तो बढ़ा सकता है, लेकिन अगली सुनवाई तक किसी भी कर्मचारी का अंतिम पदोन्नति आदेश जारी नहीं होगा।

कोर्ट ने आरक्षकों की वरिष्ठता सूची में नियमों की अनदेखी के खिलाफ दायर एक याचिका सुनवाई के बाद आदेश जारी किया है। याचिकाकर्ता सुरेंद्र कुमार देशमुख ने राज्य शासन व अन्य को पक्षकार बनाते हुए याचिका दायर की है। विवाद पुलिस मुख्यालय PHQ द्वारा खुद के अनुरोध पर ट्रांसफर होकर दूसरे जिलों में जाने वाले आरक्षकों की वरिष्ठता की गणना को लेकर है। नियमों के अनुसार, जब कोई आरक्षक स्वेच्छा से दूसरे जिले में ट्रांसफर लेता है तो उसे उस नए जिले की वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे रखा जाता है। याचिकाकर्ता की ओर से बताया कि पुलिस विभाग इस स्थापित नियम को दरकिनार कर प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। विभाग उन आरक्षकों के प्रमोशन पर भी विचार कर रहा है, जो खुद के अनुरोध पर ट्रांसफर होकर आए हैं और उनकी वरिष्ठता की गणना नए जिले में आने की तारीख से करने के बजाय उनकी शुरुआती नियुक्ति तिथि से की जा रही है। मामले की सुनवाई जस्टिस बीडी गुरु के सिंगल बेंच में हुई।

गावस्कर के ये रिकार्ड आज तक हैं बरकरार : पहले ही मैच में 700 से अधिक रन

मुम्बई। क्रिकेट की दुनिया में कई रिकार्ड बनते और टूटते रहे हैं पर कुछ रिकार्ड ऐसे हैं जो आज तक बरकरार हैं। ये रिकार्ड भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और महान बल्लेबाज रहे सुनील गावस्कर के नाम हैं। सुनील गावस्कर के अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरूआत भी शानदार थी। साल 1970-71 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू करते हुए, गावस्कर ने 700 से अधिक रन बनाकर सबको हैरान कर दिया। उन्होंने अपनी पहली टेस्ट सीरीज के 5 में से चार मैचों में रिकॉर्ड 774 रन बनाए, जिसमें चार शतक और तीन अर्धशतक शामिल थे। उनकी बल्लेबाजी औसत 154.80 रही। यह विश्व रिकार्ड पांच दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अटूट है और दुनिया का कोई भी बल्लेबाज अपनी पहली टेस्ट सीरीज में इतने रन नहीं बना पाया है।

वह अपने समय के सबसे भरोसेमंद फील्डरों में से एक थे। विशेष रूप से स्लिप और क्लोज-इन पोजीशन पर उनकी पकड़ लाजवाब थी। वह टेस्ट क्रिकेट में (एक गैर-विकेटकीपर के रूप में) 100 कैच लपकने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने, एक ऐसा मील का पत्थर जिसे सबसे पहले छूने का गौरव आज भी उन्हीं के नाम है।

सबसे तेज 5000 टेस्ट रन बनाने वाले भारतीय

उनके नाम एक ऐसा रिकॉर्ड भी दर्ज है जिसे आधुनिक युग के महानतम भारतीय बल्लेबाज जैसे सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ या विराट कोहली भी नहीं तोड़ पाए हैं। वह है सबसे तेज 5000 टेस्ट रन बनाने के। अगर वैश्विक स्तर की बात करें, तो वह इस सूची में चौथे स्थान पर आते हैं, केवल सर डॉन

ब्रैडमैन जैसे सर्वकालिक महान खिलाड़ी ही उनसे आगे हैं।

सबसे पहले 10 हजार रन

एक समय टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाना एक असंभव सपना माना जाता था पर गावस्कर ने इस रिकार्ड को तोड़ दिया। वह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में यह असंभव सा आंकड़ा सबसे पहले हासिल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने। उनसे पहले कोई भी बल्लेबाज यहां तक नहीं पहुंच सका था। मार्च 1987 में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, जिसने दुनिया को दिखाया कि लगातार रन कैसे बनाए जाते हैं।

बिन हेलमेट बल्लेबाजी

गावस्कर एक मात्र बल्लेबाज हैं जो दूनिया के सबसे तेज गेंदबाजी आक्रामणक सामने भी हमेशा बिना हेलमेट के उतरे हैं। वह साल 1970 और 80 के दशक में वह भारतीय बल्लेबाजी के मुख्य स्तंभ रहे हैं। इसी समय वेस्टइंडीज टीम क्रिकेट इतिहास की सबसे खतरनाक टीमों में से एक थी, जिसके तेज गेंदबाज (मैल्कम मार्शल, जोएल गार्नर, एंडी रॉबर्ट्स और माइकल होल्डिंग) बल्लेबाजों के दिलों में खौफ पैदा करते थे। बिना हेलमेट उनकी बाउंसर्स का सामना करना जान जोखिम में डालने जैसा था, लेकिन गावस्कर को वेस्टइंडीज की चुनौती सबसे ज्यादा रास आती थी।

वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे अधिक 13 टेस्ट का रिकार्ड

उन्होंने कैरेबियाई टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा 13 टेस्ट शतक लगाने का अटूट रिकॉर्ड दर्ज किया है। दशकों बीत जाने के बाद भी आज तक कोई बल्लेबाज इस रिकॉर्ड के आसपास भी नहीं पहुंच पाया है, जो उनके अदम्य साहस और कौशल का प्रतीक है। ये सभी रिकॉर्ड गावस्कर की असाधारण प्रतिभा, अदम्य साहस और क्रिकेट के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाते है।

वैभव को लगातार अवसर देकर एकदिवसीय विश्वकप के लिए तैयार करें : शिवरामकृष्णन

चेन्नई। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व लेग स्पिनर लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने 15 साल के उभरते हुए बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को लगातार अवसर देने को कहा है। शिवरामकृष्णन के अनुसार वैभव को आराम देने की जगह उसे लगातार खेलने दें। जिससे वह अलग-अलग हालातों के लिए तैयार हो सकें। जिससे वह अगले वर्ष होने वाले एकदिवसीय विश्व कप के लिए तैयार हो सकें।

शिवरामकृष्णन ने इस बात पर जोर दिया कि जब टीम प्रबंधन ने वैभव जैसे युवा पर भरोसा जताया है, तो उन्हें पर्याप्त अवसर भी दिए जाने चाहिए। उन्होंने कहा, उसे सीमित ओवरों के क्रिकेट में लगातार अवसर मिलने चाहिए। उसे आराम देने की कोई जरुरत नहीं है। इसकी जगह उसे पूर साल खेलना चाहिए शिवरामकृष्णन ने कहा कि वैभव अगले 20 वर्षों तक भारतीय क्रिकेट को अपनी सेवा दे सकते है। साथ ही कहा कि एक बल्लेबाज होने के नाते उसे गेंदबाजों जैसी फिटनेस प्रबंधन की जरुरत नहीं होगी। साथ ही लंबे समय तक बल्लेबाजी करने से उसकी एकाग्रता और मानसिक मजबूती भी बेहतर होगी। उन्होंने कहा, एक बार जब आप ने उसे टीम में शामिल करने का फैसला कर लिया है, तो उसे पूरा अवसर भी देना चाहिए। इस समय, वैभव को मुख्य कोच गौतम गंभीर, कप्तान श्रेयस अय्यर और टीम के बाकी खिलाड़ियों के पूरे समर्थन की जरुरत है। शिवरामकृष्णन ने सलाह दी कि यदि शुरूआती कुछ मैचों में उसका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं भी रहता है, तब भी उसे टीम में बनाये रखना चाहिये। शिवरामकृष्णन के अनुसार वैभव स्वाभाविक रूप से आक्रामक स्ट्रोक खेलने वाले बल्लेबाज हैं, और ऐसे में उनसे कुछ गलतियाँ होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि उसका सही तरीके से मार्गदर्शन किया जाए और उसे पूरा समर्थन मिले। वह ऐसा खिलाड़ी है जो कई बार जोखिम उठाएगा, लेकिन आधुनिक क्रिकेट जोखिम लेने का ही खेल है। इसलिए उसे अपनी स्वाभाविक बल्लेबाजी शैली या अपने नजरिये को बदलने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए। हालांकि उसे गेंदबाजों की रणनीति भी देखनी होगी। उन्हें परिस्थितियों के अनुसार बेहतर फैसले लेने की कला भी सीखनी होगी इसके साथ ही कहा कि उसे केवल टी20 तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उन्हें एकदिवसीय क्रिकेट में भी मौका मिलना चाहिए।

युवराज को पिता के बयानों के लिए माफी मांगने की जरुरत नहीं : कपिल

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने कहा कि युवराज सिंह को अपने पिता योगराज सिंह के विवादित बयानों को लेकर माफी मांगने की कोई जरुरत नहीं है। योगराज ने कई अवसरों पर कपिल को लेकर कई आरोप लगाए थे और कहा था कि उन्हें कपिल ने ही पहले नॉर्थ जोन फिर हरियाणा और अंत में भारतीय टीम का कप्तान बनने के बाद टीम से बाहर करवाना और उनका अंतरराष्ट्रीय करियर समाप्त किया था। उन्होंने यहां तक कहा था कि उनके बेटे युवराज के पास कपिल से अधिक ट्राफियां हैं। पिता के इस प्रकार के बयानों के लिए युवराज ने कपिल से मांफी मांगी थी। कपिल ने युवराज की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा, युवराज को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वह एक महान क्रिकेटर हैं, जिन्होंने खेल को बेहद लोकप्रिय बनाया है। रिकॉर्ड बनते-टूटते रहते हैं पर जिस में युवराज खेले, लोगों ने उन पर खूब प्यार लुटाया।

कपिल ने योगराज को अपने बचपन का दोस्त बताते हुए स्वीकार किया कि उन्हें कठोर स्वभाव के लोग पसंद नहीं हैं। उन्होंने

कहा कि जिंदगी में बहुत कुछ होता है, लेकिन व्यक्ति को हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही कहा कि योगराज के बेटे ने देश के लिए इतना अच्छा प्रदर्शन किया है, उन्हें खुश रहना चाहिए। साथ ही कहा कि किसी व्यक्ति का स्वभाव उसकी प्रतिक्रिया से पता चलता है। उन्होंने कहा, आपको जिंदगी में सब चीजें नहीं मिलतीं पर उसके कारण किसी को भी कुछ भी कह देन ठीक नहीं है। अउकर कोई उग्र प्रतिक्रिया दे तो आप क्या करेंगे।

कपिल ने योगराज को उनकी उपलब्धि याद दिलायी और कहा, कितने लोग हैं, जिन्होंने योगराज की तरह देश के लिए क्रिकेट भी खेला और अभिनय भी किया। इस तरह देखें तो उन्होंने कई लोगों से ज्यादा कुछ हासिल किया। इसके बाद भी अगर आप नाखुश हैं तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपने बचपन की दोस्ती का जिक्र करते हुए कहा, वह मेरा बचपन का दोस्त है। हम अलग-अलग रास्तों पर चले गए, तो क्या हुआ? हमने बहुत अच्छा समय बिताया। जिंदगी बदलती रहती है। हम साथ में बड़े हुए हैं और हमने बहुत अच्छा समय बिताया है।

23 जुलाई से शुरू होंगे राष्ट्रमंडल खेल

भारोत्तोलक मीराबाई चानू पर रहेंगी नजरें

नई दिल्ली। भारत की ओलंपिक पदक विजेता और स्टार भारोत्तोलक मीराबाई चानू का ध्यान अब 23 जुलाई से 2 अगस्त तक ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों पर है। इन खेलों में वह अपने पसंदीदा 48 किग्रा वर्ग में उतरेंगी, जहां उन्हें स्वर्ण पदक का प्रबल दावेदार माना जा रहा है।

राष्ट्रमंडल खेलों में उनका प्रदर्शन हमेशा ही बेहतरीन रहा है और वह एक बार फिर पोडियम पर शीर्ष स्थान हासिल करने की उम्मीद कर रही हैं। हाल ही में मोदीनगर में हुई राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उन्होंने कुल 205 किग्रा (89 किग्रा स्नैच और 116 किग्रा क्लीन एंड जर्क) भार उठाकर 48 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था, जो उनके फॉर्म को दर्शाता है।

राष्ट्रमंडल खेलों के बाद, चानू अक्टूबर में होने वाले एशियाई खेलों पर ध्यान केंद्रित करेंगी। एशियाई खेल उनके लिए एक नई चुनौती पेश करेंगे, क्योंकि इस टूनार्मेंट के लिए उन्हें 53 किग्रा वर्ग में उतरना होगा। इसके लिए उन्हें अपना वजन भी बढ़ाना होगा, जो किसी भी भारोत्तोलक के लिए एक महत्वपूर्ण समायोजन होता है। दिलचस्प बात यह है कि अपने शानदार करियर के बावजूद, मीराबाई चानू ने अब तक एशियाई खेलों में कोई पदक नहीं जीता है, जिससे यह उनके लिए एक विशेष प्रेरणा का स्रोत है।यह साल 2028 लॉस एंजिलिस ओलंपिक के लिए पहला क्वालीफाइंग टूनार्मेंट होने के कारण और भी अहम माना जा रहा है। एशियाई खेलों का प्रदर्शन न केवल पदक के लिए, बल्कि ओलंपिक क्वालीफिकेशन प्रक्रिया की शुरूआत के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। मीराबाई की अनुपस्थिति से एशियाई चैम्पियनशिप में उनकी जगह कोमल कोहर को शामिल किया जा सकता है, जिससे उन्हें भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। मीराबाई चानू अब पूरी तरह से अपनी चोट से उबरने और ग्लासगो व आइची-नागोया (में होने वाले बड़े मुकाबलों के लिए अपनी तैयारी पर ध्यान केंद्रित करेंगी, ताकि वह एक बार फिर भारत को गौरवान्वित कर सकें।

ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम ने पुरुषों को टी20 खिताब जीतने के मामले में पीछे छोड़ा

सिडनी। ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने विश्व क्रिकेट में कई बड़े रिकार्ड अपने नाम किये हैं। यहां तक कि पुरुष टीमों को भी पीछे छोड़ दिया है। ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम ने टी20 विश्व कप में जितने खिताब जीते हैं उतने भारत, पाकिस्तान और स्वयं ऑस्ट्रेलिया की पुरुष टीमों ने मिलकर भी नहीं जीते हैं। इससे साफ है कि ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम सबसे आगे हैं। ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने रिकॉर्ड सातवीं बार टी20 खिताब जीता है। टीम कुल आठ बार फाइनल में पहुंची है और उनमें से सात बार चैंपियन बनी है। इस टूनार्मेंट के इतिहास में उन्हें सिर्फ एक बार वेस्टइंडीज के खिलाफ फाइनल में हार का सामना करना पड़ा है, जो इस बात को साबित करता है कि महिला क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया का दबदबा है। ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम के इन सात टी20 विश्व कप खिताबों के मुकाबले, भारत, पाकिस्तान और खुद ऑस्ट्रेलिया की पुरुष टीमें मिलकर भी इतने खिताब नहीं जीत पाई हैं। इन तीनों दिग्गज टीमों ने अब तक कुल तीन टी20 विश्व कप खिताब जीते हैं झ भारत ने एक बार, पाकिस्तान ने एक बार और ऑस्ट्रेलिया ने भी एक बार। यदि इसमें श्रीलंका की पुरुष टीम को भी जोड़ लिया जाए, जिसने एक बार यह खिताब जीता है, तो भी कुल संख्या केवल चार तक ही पहुँचती है, जो ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम के अकेले के सात खिताबों से काफी कम है।

ऑस्ट्रेलियाई वुमेंस टीम ने पहली बार 2010 में टी20 विश्व कप जीता था। इसके बाद उन्होंने 2012 और 2014 में लगातार दो और खिताब अपने नाम किए। 2016 में उन्हें वेस्टइंडीज के हाथों फाइनल में हार मिली, लेकिन उन्होंने वापसी करते हुए 2018, 2020 और 2023 में फिर से जीत हासिल की, जिससे उन्होंने खिताबों की दूसरी हैट्रिक पूरी की।

कारोबार

मजबूत Q1 ग्रोथ अपडेट के बावजूद कल्याण ज्वैलर्स के शेयरों में 8% की गिरावट आई

कंपनी द्वारा अप्रैल-जून तिमाही के लिए मजबूत बिजनेस अपडेट की रिपोर्ट के बावजूद मंगलवार को शुरूआती कारोबार में कल्याण ज्वैलर्स इंडिया के शेयरों में लगभग 8 प्रतिशत की गिरावट आई।

यह गिरावट वृद्धि के आंकड़ों पर निवेशकों की निराशा को दशार्ती है, जो बड़े प्रतिद्वंद्वी टाइटन की तुलना में मामूली दिखाई दे रहे थे और आभूषण क्षेत्र से बढ़ी उम्मीदों के बीच आए थे। सुबह के कारोबार के दौरान स्टॉक 7.8 प्रतिशत तक गिरकर 351.55 पर आ गया, जिससे 2026 में इसकी गिरावट 27 प्रतिशत से अधिक हो गई।

यह गिरावट तब आई जब कल्याण ज्वैलर्स ने पहली तिमाही के दौरान घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों परिचालनों में स्वस्थ दोहरे अंक की वृद्धि दर्ज की। कंपनी ने कहा कि उसके भारतीय कारोबार में जून तिमाही के दौरान साल-दर-साल लगभग 38 प्रतिशत राजस्व वृद्धि दर्ज की गई। सेम-स्टोर बिक्री वृद्धि लगभग 28 प्रतिशत रही, जो मौजूदा दुकानों से मजबूत मांग का संकेत देती है। इसके अंतरराष्ट्रीय कारोबार, जो मुख्य रूप से पश्चिम एशिया के बाजारों से संचालित होता है, ने लगभग 35 प्रतिशत की राजस्व वृद्धि दर्ज की, जबकि इस क्षेत्र में तिमाही के दौरान लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कंपनी के समेकित राजस्व में अंतर्राष्ट्रीय परिचालन का योगदान लगभग 14 प्रतिशत था।

कल्याण ज्वैलर्स के डिजिटल ज्वैलरी प्लेटफॉर्म, कैंडेरे ने मजबूत गति दिखाना जारी रखा, राजस्व में साल-दर-साल 112 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तिमाही के दौरान, कंपनी ने 12 नए कल्याण शोरूम और पांच कैंडेरे स्टोर खोलकर अपने खुदरा पदचिह्न का विस्तार किया। 30 जून तक इसका कुल शोरूम नेटवर्क 524 आउटलेट्स पर था। प्रबंधन ने कहा कि कंपनी ने सकारात्मक गति के साथ दूसरी तिमाही में प्रवेश किया है, जो आगामी त्योहारी और शादी के मौसम से पहले मजबूत उपभोक्ता भावना से समर्थित है, जो आम तौर पर उच्च आभूषण मांग को बढ़ाता है। हालाँकि, बाजार की प्रतिक्रिया धीमी रही क्योंकि निवेशक कल्याण ज्वैलर्स के प्रदर्शन को टाइटन के हालिया तिमाही अपडेट के मुकाबले बेंचमार्क करते दिखे। टाइटन ने उपभोक्ता व्यवसाय राजस्व में 41 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जिसके कारण उसके आभूषण खंड में 39 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में भी साल-दर-साल 128 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि दर्ज की गई, जिससे घोषणा के बाद इसके शेयरों में 3.5 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। विश्लेषकों ने कहा कि कल्याण ज्वैलर्स ने ठोस परिचालन वृद्धि प्रदान की है, लेकिन मजबूत क्षेत्र-व्यापी गति के कारण निवेशकों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। कंपनी का विस्तारित स्टोर नेटवर्क, अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति और डिजिटल विकास प्रमुख सकारात्मकताएं बनी हुई हैं, लेकिन बाजार सहभागी बारीकी से इस पर नजर रख रहे हैं कि क्या विकास दर बड़े उद्योग के खिलाड़ियों द्वारा निर्धारित गति से मेल खा सकती है।

सोने और चांदी में लगातार दूसरे दिन गिरावट

करीब 1.20 प्रतिशत तक घटे दाम

मुंबईः सोने और चांदी मंगलवार को लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ खुले। इससे दोनों कीमती धातुओं का दाम करीब 1.20 प्रतिशत तक कम हो गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने के 5 अगस्त 2026 का कॉन्ट्रैक्ट पिछली क्लोजिंग 1,46,917 रुपए प्रति 10 ग्राम के मुकाबले हल्की गिरावट के साथ 1,46,566 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। शुरूआती कारोबार में ही इसमें गिरावट देखने को मिली। सुबह 9:52 पर यह 1,009 रुपए या 0.69 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 1,45,908 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। अब तक के कारोबार में सोने ने 1,45,767 रुपए प्रति 10 ग्राम का न्यूनतम स्तर और 1,46,566 रुपए प्रति 10 ग्राम का उच्चतम स्तर छुआ है।

चांदी में गिरावट देखी जा रही है। चांदी का 4 सितंबर 2026 का कॉन्ट्रैक्ट पिछली क्लोजिंग 2,36,099 रुपए प्रति किलो के मुकाबले 1,999 रुपए की गिरावट के साथ 2,34,100 रुपए प्रति किलो पर खुला। शुरूआत कारोबार के बाद इसमें और बिकवाली देखने को मिली। यह 2,816 रुपए या 1.19 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 2,33,283 रुपए पर था। अब तक के कारोबार में चांदी ने 2,32,862 रुपए का न्यूनतम स्तर और 2,34,100 रुपए का उच्चतम स्तर छुआ है, जो कि इसका ओपनिंग लेवल भी है।

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी सोने और चांदी में बिकवाली देखने को मिल रही है। खबर लिखे जाने तक कॉमेक्स पर सोना 0.63 प्रतिशत की गिरावट के साथ 4,141 डॉलर प्रति औंस और चांदी 1.46 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 61.41 डॉलर प्रति औंस पर था। इसके अतिरिक्त, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 27) की अप्रैल-जून अवधि में गोल्ड लोन सबसे बड़ी सिक्योर एसेट क्लास बन गई है। इसने वाहन लोन को भी पीछे छोड़ दिया है। रिपोर्ट में बताया गया कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जारी किए गए सभी सिक्योर लोन में से गोल्ड लोन की हिस्सेदारी बढ़कर करीब 31 प्रतिशत हो गई है।

आपूर्तिकताओं की दिवालिया याचिका के बाद ओला इलेक्ट्रिक के शेयर 5% गिरे

नई दिल्ली। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर सोमवार को इंट्रा-डे ट्रेड में 5 परसेंट से ज्यादा गिर गए, जब एक रिपोर्ट में कहा गया कि इसकी ऑपरेटिंग ब्रांच के दो सप्लायर ने 40 करोड़ रुपये से ज्यादा के कथित बकाया को लेकर इन्सॉल्वेंसी प्रोसिडिंग की मांग करते हुए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (ठउछळ) का दरवाजा खटखटाया है। ओला इलेक्ट्रिक का शेयर प्राइस 5.3 परसेंट तक गिरकर इंट्रा-डे लो 42.10 रुपये प्रति शेयर पर आ गया। दोपहर 12 बजे, स्टॉक 5.02 परसेंट नीचे ट्रेड कर रहा था, जबकि बेंचमार्क निफ्टी इंडेक्स 0.78 परसेंट ऊपर था।

कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्टर्लिंग और एनेर्वाल्व मैंडो, जो ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के दोनों सप्लायर हैं, ने 40 करोड़ रुपये से ज्यादा के बकाया को लेकर कंपनी के खिलाफ

इन्सॉल्वेंसी प्रोसिडिंग की मांग करते हुए ठउछळ का दरवाजा खटखटाया है। रिपोर्ट में ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज की मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स (टउअ) में की गई फाइलिंग का हवाला देते हुए कहा गया है कि स्टर्लिंग को 29.8 करोड़ रुपये और एनेर्वाल्व को 10.8 करोड़ रुपये का बकाया 45 दिनों से ज्यादा समय से नहीं चुकाया गया है। कहा जाता है कि पेमेंट में देरी की वजह से दोनों कंपनियों ने ट्रिब्यूनल के सामने इन्सॉल्वेंसी की कार्रवाई शुरू की।

रिपोर्ट के मुताबिक, ठउछळ की बेंगलुरु बेंच सोमवार, 6 जुलाई को स्टर्लिंग की पिटीशन पर सुनवाई करेगी, जो एनेर्वाल्व मांडो की पिटीशन पर सुनवाई के लगभग एक महीने बाद है। यह डेवलपमेंट इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने वाली कंपनी से जुड़ा सबसे नया सप्लायर-रिलेटेड विवाद है। यह 2025 में कंपनी की एक गाड़ी रजिस्ट्रेशन एजेंसी द्वारा पेमेंट से जुड़े मामलों पर फाइल की गई इसी तरह की इन्सॉल्वेंसी पिटीशन के बाद हुआ है। पिछले पांच दिनों में, शेयर लगभग फ्लैट रहे, जिसमें 1.14 रुपये या 2.79 परसेंट की बढ़त हुई। पिछले एक महीने में, शेयरों में 2.39 रुपये या 5.38 परसेंट की गिरावट आई। पिछले छह महीनों में, स्टॉक ने नेगेटिव रिटर्न दिया, जो 1.54 रुपये या 3.53 प्रतिशत गिर गया।

भारतीय शेयर बाजार सपाट खुला, आईटी स्टॉक्स में खरीदारी

मुंबईः भारतीय शेयर बाजार मंगलवार के कोराबारी सत्र में सपाट खुला। सुबह 9:17 पर सेंसेक्स 90 अंक या 0.12 प्रतिशत की मामूली तेजी के साथ 78,375 और निफ्टी 27 अंक या 0.11 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,457 पर था। शुरूआती कारोबार में बाजार की तेजी का नेतृत्व आईटी स्टॉक्स कर रहे थे।

सूचकांकों में निफ्टी आईटी करीब एक प्रतिशत की बढ़त के साथ टॉप गेनर था। निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी सर्विसेज, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी ऑयलएंडगैस, निफ्टी हेल्थकेयर, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी ऑटो और निफ्टी प्राइवेट बैंक हरे निशान में था।

दूसरी तरफ निफ्टी मेटल, निफ्टी इंडिया डिफेंस, निफ्टी मीडिया, निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, निफ्टी पीएसई और निफ्टी कमोडिटीज लाल निशान में थे। लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में भी सपाट कारोबार हो रहा था। निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 19,315 पर करीब सपाट था। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 62 अंक या 0.10 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 62,356 पर था। सेंसेक्स पैक में इन्फोसिस, टाइटन, एचसीएल टेक, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एसबीआई, इटरनल, बजाज फिनसर्व, अदाणी पोर्ट्स, एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, एचयूएल, पावर ग्रिड, अल्ट्राटेक सीमेंट, मारुति सुजुकी और एचयूएल हरे निशान में थे। ट्रेंट, इंडिगो, बीईएल, एलएंडटी, टाटा स्टील, एशियन पेंट्स, आईसीआईसीआई बैंक, सन फार्मा और आईसीआईसीआई बैंक लाल निशान में थे।

ज्यादातर एशियाई बाजारों में गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। टोक्यो, शंघाई, हांगकांग, बैंकॉक और सोल लाल निशान में थे। वहीं, जकार्ता में तेजी थी। अमेरिकी शेयर बाजार सोमवार को हरे निशान में बंद हुए थे। इसमें मुख्य सूचकांक डाओ जोन्स 0.29 प्रतिशत की बढ़त के साथ और टेक्नोलॉजी इंडेक्स नैस्डैक 1.12 प्रतिशत की मजबूती बढ़त के साथ बंद हुआ। बाजार के जानकारों ने कहा कि बाजार में तेजी के साफ संकेत दिख रहे हैं। दो बातें जो भारतीय बाजार पर दबाव डाल रही थीं, जिसमें कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और एफपीआई की लगातार बिकवाली शामिल हैं, अब पीछे छूट गई हैं और स्थिति बदल गई है। कच्चे तेल की कीमतें युद्ध से पहले के स्तर पर आ गई हैं और एफपीआई अब खरीदार बन गए हैं।

विदेशी निवेशकों की खरीदारी अभी कोई मजबूत ट्रेंड नहीं है, लेकिन उनका बिकवाली रोककर खरीदार बन जाना एक अहम बदलाव है, जिसके फंडामेंटल के सहारे आगे भी बने रहने की उम्मीद है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने सोमवार को 243.03 करोड़ रुपए निवेश किए थे। इस दौरान घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 3,791.42 करोड़ रुपए का निवेश इक्विटी में किया।

महत्वपूर्ण ख़बर

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कैप्टन विक्रम बत्रा को श्रद्धांजलि अर्पित की

- भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने परमवीर चक्र से सम्मानित, कैप्टन विक्रम बत्रा के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने संदेश में कहा कि कैप्टन बत्रा कारगिल युद्ध में शत्रुओं पर काल की भांति टूट पड़े और मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। उनका शौर्य सदैव राष्ट्रसेवा की ऊर्जा प्रदान करता रहेगा।

शासकीय छात्रावासों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 जुलाई तक

- भोपाल। राज्य शिक्षा केन्द्र, स्कूल शिक्षा विभाग ने संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालक/बालिका शासकीय छात्रावासों में रिक्त स्थानों पर प्रवेश के लिए अंतिम चरण में 20 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। इस वर्ष से प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन की गई है। इसके लिए विभाग ने एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से विशेष होस्टल प्रबंधन प्रणाली विकसित की है।

संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र श्री हरजिंदर सिंह ने बताया कि, प्रदेश में संचालित छात्रावासों में विशेष रूप से वंचित वर्गों की बालिका/बालक को उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के लिए पारदर्शी ऑनलाइन प्रवेश प्रणाली प्रारंभ की गई है।

निजी स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश के लिए तीसरे चरण की प्रक्रिया प्रारंभ

- भोपाल। प्रदेश में शिक्षा का अधिकार कानून अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2026-27 में निजी स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश के लिए तीसरे चरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके अंतर्गत 8 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र, स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक को निर्देश भी जारी कर दिए हैं।

उल्लेखनीय है कि कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के अंतर्गत पात्र बच्चों को अशासकीय, गैर-अनुदान प्राप्त निजी विद्यालयों में नि:शुल्क प्रवेश दिया जाता है, जिसका शुल्क प्रदेश सरकार वहन करती है। प्रदेश में आरटीई के अंतर्गत प्रथम एवं द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। द्वितीय चरण की प्रक्रिया के बाद जिन विद्यालयों में सीटें रिक्त रह गई हैं, उन सभी विद्यालयों को उनकी रिक्त सीटों सहित द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया के लिए पोर्टल पर प्रदर्शित किया गया है।

दुग्ध उत्पादन में प्रदेश को बनायेंगे देश का अव्वल राज्य

उन्नत खेती व पशुपालन से बढ़ायेंगे किसानों की आमदनी : मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किसानों की आमदनी केवल एक फसल से नहीं बल्कि बहु फसलों एवं उन्नत पशुपालन से बढ़ेगी। इस बात को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा उन्नत व प्राकृतिक खेती के साथ-साथ पशुपालन को विशेष बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में मध्यप्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश में तीसरे स्थान पर है। हम अगले पाँच वर्षों में मध्यप्रदेश को दुग्ध उत्पादन में नम्बर वन राज्य बनायेंगे। इसी कड़ी में सरकार नेशनल डेयरी विकास योजना के तहत ग्वालियर दुग्ध संघ सहित साँची दुग्ध उत्पादन संघ को भरपूर मदद दे रही है। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को ग्वालियर में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्नत कृषि पर हुई संभागीय कार्यशाला में मौजूद किसानों से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कार्यशाला में किसानों से सीधा संवाद करते हुए जैविक व प्राकृतिक खेती पर अनुभव सुने।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ग्वालियर में मूर्तरूप लेने जा रही अत्याधुनिक हाईटेक नर्सरी एवं फ्लोरीकल्चर गार्डन का भी रिमोट से भूमिपूजन किया। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से ग्वालियर के खुरैरी एवं ग्राम जहांगीरपुर में इस हाईटेक नर्सरी के प्रथम चरण का कार्य होने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उद्यानिकी, मत्स्य पालन एवं कृषि से जुड़े अन्य विभागों की योजनाओं के तहत विभिन्न किसानों को हितलाभ भी वितरित किए। कार्यक्रम में किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री एदल सिंह कंषाना, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्क्रण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह, ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री जयभान सिंह पवैया, सांसद श्री भारत सिंह कुशवाह, विधायक श्री मोहन सिंह राठौर व श्रीमती सरला रावत, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती दुर्गेश कुँवर सिंह जाटव, अपेक्स बैंक के प्रशासक श्री महेन्द्र सिंह यादव, पूर्व सांसद श्री विवेक नारायण शेजवलकर, पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के अध्यक्ष श्री केशव सिंह बघेल, साडा अध्यक्ष श्री अशोक शर्मा, मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री अशोक जादौन, नगर निगम सभापति श्री मनोज तोमर, श्री जयप्रकाश राजौरिया, किसान मोर्चा के पदाधिकारी श्री गिर्राज व्यास व श्री अमरदीप सिंह औलख सहित जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में शामिल रहे।

सिंचाई रकबा होगा 100 लाख हैक्टेयर तक

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2023 के बाद सिंचाई रकबे में बड़ी बढ़ोत्तरी हुई है। वर्ष 2003 में प्रदेश का सिंचाई रकबा मात्र साढ़े 7 लाख हैक्टेयर था जो अब बढ़कर लगभग 50 लाख हैक्टेयर हो गया है। इसे हम 100 लाख हैक्टैयर तक ले जायेंगे। चंबल-पार्वती-काली सिंध एवं केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजनाओ के माध्यम से यह संभव हुआ। उन्होंने इन परियोजनाओं की मंजूरी के लिये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रति प्रदेशवासियों की ओर से विशेष रूप से आभार व्यक्त किया। किसानों से संवाद के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अब प्रदेश के कृषकों को 31 मार्च तक ऋण जमा करने की चिंता नहीं रही है। सरकार ने अब उन्हें ऋण जमा करने के लिये पूरे एक साल का मौका दिया है। उन्होंने कहा कि किसान कल्याण वर्ष में सरकार द्वारा सभी प्रकार के कृषि उत्पादों व पशुपालन को बढ़ावा देने के साथ किसानों की सहूलियतों का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है।

खिड़क प्रणाली के स्थान पर गौ-शालाओं की स्थापना

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गौ माता कभी आवारा नहीं हो सकती। इसी भाव के साथ प्रदेश सरकार द्वारा गौ संरक्षण एवं स्वदेशी गाय पालन को विशेष बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार ने इसी कड़ी में नगरीय क्षेत्रों में निराश्रित गायों को बंद करने के लिये कार्यरत खिड़क प्रणाली को समाप्त कर दिया है और बड़े पैमाने पर गौशालायें स्थापित की जा रही हैं। साथ ही देशी गायों में नस्ल सुधार के प्रयास भी प्रमुखता से किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्वालियर की लाल टिपारा गौशाला की तरह प्रदेश के महानगर इंदौर, उज्जैन, जबलपुर व भोपाल में बड़ी गौशालाओं की स्थापना की जा रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय परिसर में समन्वित कृषि प्रणाली इकाई एवं बहु-स्तरीय कृषि पद्धति इकाई का लोकार्पण भी किया। किसानों के लिए आधुनिक, टिकाऊ एवं लाभकारी खेती का व्यावहारिक मॉडल कृषि विश्वविद्यालय ने विकसित किया है। इस ह्लसमन्वित कृषि प्रणाली इकाईह्व में फसल उत्पादन, बागवानी, डेयरी, बकरी पालन, कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन तथा जैविक खाद निर्माण जैसी गतिविधियों को एकीकृत किया गया है। इस मॉडल में एक गतिविधि का अपशिष्ट दूसरी गतिविधि के लिए रॉ मटेरियल बनता है, जिससे लागत घटती है। साथ ही संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है और किसानों को आय के अनेक स्त्रोत प्राप्त होते हैं। इसी तरह ह्लबहु-स्तरीय कृषि पद्धति इकाईह्व में एक ही खेत में विभिन्न ऊँचाई वाली फसलों का वैज्ञानिक संयोजन विकसित किया गया है। इससे भूमि, जल, पोषक तत्वों और सूर्य के प्रकाश का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित होता है। किसान एक ही खेत से पूरे वर्ष विविध फसलों का उत्पादन लेकर अधिक आय अर्जित कर सकते हैं। कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरू प्रो. अरविंद कुमार शुक्ला ने बताया कि विश्वविद्यालय ने इन दोनों इकाइयों को जीवंत प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन मॉडल के रूप में विकसित किया है। यहां प्रशिक्षण प्राप्त कर किसान अपने खेतों में इन तकनीकों को अपना सकेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सड़क सुरक्षा के उपहार स्वरूप जिले के लगभग 50 लोगों को हेलमेट वितरित किए। साथ ही सभी से आग्रह किया कि हेलमेट पहनकर वाहन चलाएं और दूसरों को भी इसके लिये प्रेरित करें। प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप जिला प्रशासन द्वारा सड़क सुरक्षा के लिये अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा हेलमेट वितरित किए गए। कृषि विश्वविद्यालय परिसर में समन्वित कृषि प्रणाली के तहत मॉडल स्वरूप बनाए गए बहुउद्देश्यीय तालाब में जब मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दाने डालकर तालाब के दूसरे छोर पर तैर रहीं बतखों को पुकारा तो बतखें उनके नजदीक आ गईं और बड़े चाव के साथ दानों को खाया। उल्लेखनीय है कि इस तालाब को कृषि विश्वविद्यालय परिसर के भवनों से जुड़ीं वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं से भरा जाता है। तालाब के ऊपर एक बड़ा मुर्गी पालन बॉक्स बनाया गया है। मुर्गियों के चूजों की बीट इस तालाब में गिरती है जिसे मछलियां व बतखें खाती हैं। इस प्रकार एक संरचना से सफलतापूर्वक मुर्गी, मछली व बतख पालन किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कृषि विश्वविद्यालय परिसर में ह्लएक पेड़ माँ के नामह्व अभियान के तहत आम का पौधा रोपा। उन्होंने इस अवसर पर वृहद स्तर पर पौधे रोपने और उनकी सुरक्षा करने का आह्वान किया। मंत्रिगण श्री ऐदल सिंह कंषाना व श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सांसद श्री भारत सिंह कुशवाह व विधायक श्री मोहन सिंह राठौर सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी पौधे रोपे। कार्यक्रम में संभाग भर से आए प्रगतिशील किसान, जनप्रतिनिधिगण एवं संभाग आयुक्त श्री मनोज खत्री, पुलिस महानिरीक्षक श्री अरविंद कुमार सक्सेना, कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री धर्मवीर सिंह एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सोजान सिंह रावत सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

जैविक व प्राकृतिक खेती पर किसानों ने किए अनुभव साझा

उन्नत कृषि पर आयोजित हुई संभागीय कार्यशाला में कृषकों ने भी अपने अनुभव साझा किए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इन सभी कृषकों को अपने पास बुलाया और उत्साहवर्धन किया। ग्वालियर जिले के ग्राम बिलौआ निवासी उन्नत कृषक प्राण सिंह माथुर ने अपने अनुभव सुनाते हुए कहा कि वे अपने छोटे से कृषि फार्म में सफलतापूर्वक प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। उन्होंने पाँच नए किस्म के पौधों की खोज की है, जिसे वैज्ञानिक स्तर पर मान्यता मिल चुकी है। उनके द्वारा ईजाद किए गए अमरूद की बिलौआ-22 व बिलौआ-रेड किस्म पेटेंट हो चुकी हैं। प्राण सिंह अब तक 50 हजार से अधिक कृषकों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दे चुके हैं। इसी तरह ग्राम देवरा निवासी बृजेन्द्र रावत ने बताया कि उन्होंने रासायनिक खेती छोड़कर पूरी तरह प्राकृतिक खेती को अपना लिया है। उन्नत प्राकृतिक खेती के लिये उनकी धर्मपत्नी को राष्ट्रीय स्तर पर पाँच अवार्ड मिल चुके हैं। भगवानपुरा मुरार निवासी कृषक श्री देवराज कुशवाह का कहना था कि वे अब प्राकृतिक पद्धति से गेहूँ व सरसों जैसी खाद्यान्न फसलों का उत्पादन कर रहे हैं। इसके अलावा वे भिंडी, गेहूँ, मिर्च व आलू जैसी फसलें भी पैदा करते हैं।

नवचयनित राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को डीजीपी का मार्गदर्शन

ईमानदारी और सत्यनिष्ठा एक युवा अधिकारी की सबसे बड़ी पूंजी है- डीजीपी श्री मकवाणा

भोपाल। मध्यप्रदेश संवर्ग 2025 बैच के 08 परिवीक्षाधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने आज पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाणा से सौजन्य भेंट की। डीजीपी श्री मकवाणा ने सभी अधिकारियों से परिचय प्राप्त कर उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण पूरी तन्मयता से प्राप्त करें ताकि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का उत्कृष्ट निष्पादन कर सकें। उन्होंने कहा कि वे अपने अधीनस्थ अमले से भी सीखने में संकोच न करें।

पुलिस महानिदेशक ने नवचयनित अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रशासनिक सेवा केवल एक पद नहीं, बल्कि जनता की सेवा का दायित्व है। उन्होंने अधिकारियों से ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में नए आपराधिक कानून, साइबर सुरक्षा, साइबर फ्रॉड, नारकोटिक्स एवं नशा मुक्ति जैसे विषय प्रशासनिक अधिकारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। बदलती चुनौतियों को देखते हुए अधिकारियों को निरंतर सीखते रहने और तकनीक का प्रभावी उपयोग करने की आवश्यकता है। डीजीपी ने अपने सेवाकाल के अनेक अनुभव साझा किए। उन्होंने मंदसौर की एक घटना का उल्लेख करते हुए बताया कि कठिन परिस्थितियों में धैर्य, संवाद और सही नेतृत्व से बड़ी से बड़ी भीड़ को भी शांतिपूर्वक नियंत्रित किया जा सकता है। उन्होंने मुरैना में पदस्थापना के दौरान सड़क सुरक्षा अभियान और निष्पक्ष जांच के अनुभव भी साझा किए।

उन्होंने बताया कि डायल-100 से 112 आपातकालीन सेवा में परिवर्तन आसान नहीं था। लगभग छह से सात महीने के अथक प्रयासों, टीमवर्क और समर्पण से इस व्यवस्था को सफलतापूर्वक लागू किया गया। उन्होंने कहा कि किसी भी बड़े परिवर्तन के लिए धैर्य और सतत प्रयास आवश्यक हैं। नक्सल चुनौती का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश ने वर्ष 2025 में नक्सल समस्या से मुक्ति प्राप्त की। यह सुरक्षा बलों, प्रशासन और जनता के समन्वित प्रयासों का परिणाम है।

राज्य सरकार इसी माह समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में है अग्रसर

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जनसंघ के संस्थापक और प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक, श्रद्धेय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर लालघाटी स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर पौधरोपण किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्मरण करते हुए कहा कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पूरे सम्मान के साथ मनाई जा रही है। डॉ. मुखर्जी के 'एक देश-एक विधान-एक निशान-एक प्रधान' के संकल्प को साकार करने की दिशा में मध्यप्रदेश सरकार निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में राज्य सरकार इसी माह समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में अग्रसर है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए विश्व में विशेष पहचान बनाई है। डॉ. मुखर्जी ने देश और समाज के सर्वांगीण विकास की कल्पना की। राज्य सरकार ने डॉ. मुखर्जी की जयंती के अवसर पर 15 दिवसीय जनकल्याण पखवाड़े की शुरूआत की है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के सभी गरीब, जरूरतमंद और पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जा रहा है। राज्य सरकार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए औद्योगिक विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। इस दिशा में रोजगार के अवसर सृजित होने से हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित हो पा रहा है।

हर क्षेत्र में तेजी से विकास करते हुए आगे बढ़ रहा है मध्यप्रदेश

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निर्देशानुसार बना दिल्ली में बना भारत मंडपम हमारे लिए एक आदर्श उदाहरण है। डॉ. मुखर्जी की जयंती पर आज भोपाल के सतगढ़ी में मध्यप्रदेश के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर और सतगढ़ी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क की आधारशिला रखी जा रही है। राज्य सरकार कुशाभाऊ ठाकरे सभागार के पास एक आधुनिक कन्वेंशन सेंटर तैयार कर रही है, जिसकी क्षमता 5 हजार सीट्स की रहेगी। सतगढ़ी में बनने वाले नए विशाल कन्वेंशन सेंटर में 10 हजार से अधिक व्यक्तियों की व्यवस्था है। भोपाल सबसे समृद्ध और सशक्त राजधानी बनने जा रहा है। हमारा प्रदेश हर क्षेत्र में तेजी से विकास करते हुए आगे बढ़ रहा है।

सतगढ़ी क्षेत्र भोपाल के आस-पास नया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम

सतगढ़ी औद्योगिक क्षेत्र भोपाल की विकास यात्रा में होगा मंदिर के समान: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर भोपाल को सतगढ़ी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क और कन्वेंशन सेंटर की बड़ी सौगात मिली है। यह इंडस्ट्रियल पार्क देश के पहले उद्योग मंत्री डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से जाना जाएगा। सतगढ़ी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क में 15 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। सतगढ़ी क्षेत्र औद्योगिक विकास की दिशा में एक मंदिर के समान होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हम जो कहते हैं, करके दिखाते हैं। प्रदेश में विकसित हो रहे औद्योगिक क्षेत्र हमारे किसानों के लिए भी समृद्धि का द्वार खोलेंगे। युवाओं को रोजगार मिलेगा। गारमेंट इंडस्ट्री से कपास उत्पादक किसानों को लाभ मिलेगा। हमारी सरकार खेत से कारखाने और उद्योग को बाजार से जोड़ने के लिए कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपनी अलग पहचान बना रहा है। उन्होंने गरीब, अन्नदाता, युवा और नारी कल्याण पर विशेष ध्यान दिया है। राज्य सरकार प्रदेश के हर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर सोमवार को भोपाल के कोलार क्षेत्र स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र का भूमिपूजन और शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे।

समाज के हर वर्ग के लिए एक जैसा होना चाहिए कानून

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 'एक देश - एक विधान - एक निशान - एक प्रधान' की बात कही थी। उनके इस संकल्प को साकार करने के लिए राज्य सरकार इसी माह समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। समाज के हर वर्ग के लिए कानून एक जैसा होना चाहिए। प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि यूसीसी मध्यप्रदेश में लागू होगा। इसके लिए कमेटी ने सभी धर्म-समुदाय के सुझाव लिए गए, जिससे किसी के साथ भेदभाव न हो। देश के बड़े राज्यों में, मध्यप्रदेश समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य होगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी के मार्गदर्शन में हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सतगढ़ी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क से राजाभोज विमानतल की दूरी महज 25 किलोमीटर है। रानी कमलापति स्टेशन भी मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है। भोपाल का वेस्टर्न बायपास भी यहीं से गुजरेगा। सतगढ़ी के 25 एकड़ क्षेत्र में 10 हजार क्षमता वाला एक आधुनिक कन्वेंशन सेंटर भी बनेगा। यह प्रदेश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर होगा। मध्यप्रदेश अपने औद्योगिक विकास और पारदर्शी व्यवस्था के साथ तेजी से आगे बढ़ता जाएगा। सागर ग्रुप के श्री सुधीर अग्रवाल सतगढ़ी में 100 करोड़ का निवेश करेंगे। भोपाल प्राकृतिक सुंदरता और झील-तालाबों की नगरी है, लेकिन अब यह स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क भी राजधानी की पहचान बनेगा। अनेक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। भोपाल औद्योगिक नगरी के रूप में नई पहचान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यहां से प्रदेश के विकास का नया सूर्योदय हो रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक अंचल में देश-दुनिया के निवेशक औद्योगिक इकाइयां स्थापित कर रहे हैं। पिछले रविवार को शिवपुरी में 2500 करोड़ लागत से रक्षा क्षेत्र की बड़ी औद्योगिक ईकाई का भूमि-पूजन किया है। यहां बनने वाली मिसाइलों की क्षमता 1000 किलोमीटर की होगी। इससे पहले मुरैना को सोलर सेक्टर की बड़ी सौगात दी है। रोजगार आधारित उद्योगों के लिए गुना में 2 हजार करोड़ रुपये का सीमेंट प्लांट भी बनाया जा रहा है। विकसित भारत @2047 के संकल्प की पूर्ति में मध्यप्रदेश विकास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भोपाल में पहली बार जीआईएस जैसे बड़ा आयोजन संपन्न हुआ, जिसे प्रधानमंत्री श्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का आशीर्वाद मिला। जीआईएस 2025 में आए 30 लाख करोड़ रुपये के निवेश में से 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश धरातल पर आ चुका है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसान कल्याण वर्ष में जनवरी से लेकर अब तक निवेशकों के साथ 86 हजार करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। प्रदेशभर में हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रदेश की बहनों को भी हर महीने सौगात मिल रही है, अब तक मुख्यमंत्री लाड़ली बहन योजना में राज्य सरकार 50 हजार करोड़ से अधिक राशि लाड़ली बहनों को जारी कर चुकी है। बहनें रोजगार आधारित उद्योगों में काम करेंगी तो उन्हें 5000 रुपए अलग से मिलेगा।

अब मध्यप्रदेश की धरती पर बनेंगे

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश ने रक्षा क्षेत्र में नया इतिहास रचा है। अब रक्षा क्षेत्र के कई उपकरण, मिसाइल और हथियार मध्यप्रदेश की धरती पर बनेंगे। चंबल की धरती सालों से मां भारती की सेवा करने वाले वीर सैनिकों की भूमि रही है। अब यहां आधुनिक हथियार भी तैयार किए जाएंगे। यह मिसाइल एक हजार किलोमीटर तक दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त करने की क्षमता वाली होंगी। कार्यक्रम में खेल एवं युवा कल्याण तथा सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग, प्रदेश अध्यक्ष एवं वरिष्ठ विधायक श्री हेमंत खंडेलवाल, विधायक श्री रामेश्वर शर्मा, श्री रवीन्द्र यति, जनप्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

संपादकः अली आदिल खान द्वारा सांई प्रिंटिंग प्रेस डी-85, न्यू अशोक अगर, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, यूपी से मुद्रित कराकर सी-148, साउथ मोती बाग,पो. चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021 से प्रकाशित किया।
RNI No.: DELMUL/2012/47011 | Email:timesofpedia@gmail.com | समाचार चयन एवं प्रकाशन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार तथा समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन होंगे।